आज का विचार

सोच का प्रभाव मन पर होता है। मन का प्रभाव तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए, सदा अच्छा सोचें और खुश रहें।

दैनिक सिटी दर्पण

आईना सच का

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ | बुधवार, 6 मई, 2026 वर्ष 24, अंक 108, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 www.citydarpan.com

भगवंत मान ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, पंजाब के गद्दार राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की मांग की

ये सात सांसद इलेक्टेड नहीं, बल्कि सेलेक्टेड हैं; उनका किसी दूसरी पार्टी में जाना देशभक्ति नहीं, बल्कि पंजाब के साथ विश्वासघात है: मान

सिटी दर्पण संवाददाता

नई दिल्ली/पंजाब

पंजाब में दल-बदल की लड़ाई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज सर्वोच्च संवैधानिक पद तक ले गए और राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने पंजाब के गद्दार (दल-बदल करने वाले) राज्यसभा सदस्यों की सदस्यता तुरंत रद्द करने की मांग की। पार्टी की एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रपति भवन में हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि पंजाब में केवल दो विधायक होने के बावजूद भाजपा के राज्यसभा सदस्यों की संख्या में नाटकीय वृद्धि लोकतांत्रिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाती है।

- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब के सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे

सात सांसदों को इलेक्टेड नहीं, बल्कि सेलेक्टेड बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनके दल-बदल को पंजाब के साथ विश्वासघात करार दिया। उन्होंने इन सदस्यों को इस्तीफा देने और नया जनादेश लेने की चुनौती दी और चेतावनी दी कि न तो केंद्रीय एजेंसियां और न ही राजनीतिक ताकत गलत कामों को बचा सकेंगी। उन्होंने घोषणा की कि ऑपरेशन लोटस जैसे प्रयास पंजाब में कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि पंजाब कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करता।

अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बैठक के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, आज दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रहे लोकतंत्र के कत्ल के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से उठाई। राजनीतिक दलों को असंवैधानिक तरीके से तोड़ना और भाजपा की वॉशिंग मशीन में दागी नेताओं को साफ करने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हमारे लोकतांत्रिक ढांचे पर सीधा हमला है।

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन लोटस की घिनौनी चालें पंजाब में कभी सफल नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज हैं और पंजाब के लोग कभी भी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका जन सेवक होने के नाते, मैं हर पंजाबी को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों के जनादेश की रक्षा और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए अपने अंतिम सांस तक लड़ेंगे।राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, राज्यसभा के सात सदस्यों के दल-बदल से लोकतंत्र का कत्ल हुआ है। यह असंवैधानिक है क्योंकि या तो पूरी पार्टी को प्रस्ताव पास करना चाहिए था, लेकिन इन सात सांसदों ने असंवैधानिक तरीके से अपनी निष्ठा बदल ली, जिससे लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने आगे कहा, भाजपा के पास दो विधायक हैं लेकिन सात राज्यसभा सांसद हैं, जो संविधान का मजाक है। इन सांसदों को उस नई पार्टी में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, जिसकी वे पहले निंदा करते थे।

व्यवस्था में सुधार की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि सांसद को वापस बुलाने का प्रावधान किया जा सके, जैसा कि राघव चड्ढा मांग करते रहे थे ताकि इन सांसदों को देशद्रोह के लिए सजा दी जा सके।

गुरु साहिब की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें नागरिकः नायब सैनी

मुख्यमंत्री ने 8 जून को प्रदेश से भव्य सोमनाथ यात्रा निकालने की घोषणा की

भूपेंद्र शर्मा

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि 8 जून, 2026 को प्रदेश से भव्य सोमनाथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर हमारी अखंड आस्था, सांस्कृतिक धरोहर और आत्मसम्मान के पुनर्जागरण का प्रतीक है। भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक भगवान श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की पावन भूमि के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था है। भारत सरकार द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व - 1000 वर्ष की अखंड आस्था के अंतर्गत 11 जनवरी, 2027 तक एक वर्षव्यापी राष्ट्रीय स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के दर्शन के लिए जा रहे यात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों से बातचीत कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस पवित्र यात्रा पर जा रहे यात्रियों को संकल्प दिलवाते हुए कहा कि वो गुरु साहिब की

शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। यही इस यात्रा की सच्ची सफलता होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री को स्मृत्ति चिह्न, सरोपा भेंटकर सम्मानित किया गया।

श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जो ट्रेन कुरुक्षेत्र से जा रही है वह दो महान तीर्थ स्थलों के बीच सेतु का काम कर रही है। एक तरफ धर्मक्षेत्र-कुरुक्षेत्र है, जहां भगवान श्रीकृष्ण जी ने मोहग्रस्त अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश देकर जीवन का मार्ग दिखाया। यही नहीं, यह पावन धरा गुरु साहिबान के पावन चरणों से भी अनेक बार पवित्र हुई है। दूसरी तरफ, सचखंड श्री हुजूर साहिब, नांदेड़ वह पवित्र स्थान है, जहां दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए। इन दोनों पवित्र स्थलों को जोड़ने वाली यह विशेष ट्रेन भारत की आध्यात्मिक धारा के प्रवाह का प्रतीक बन रही है।

उन्होंने कहा कि तीर्थ यात्राएं धार्मिक कार्यक्रम के साथ-साथ समाज को जोड़ने का माध्यम होती हैं। यह लोगों को संस्कारों से और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम होती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री आनंदपुर साहिब- श्री फतेहगढ़ साहिब- श्री चमकौर साहिब-फिरोजपुर अमृतसर- खटकड़ कलां कलानौर- पटियाला विरासत सर्किट के विकास को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में गत 25 नवम्बर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समागम में शामिल होकर उन्हें नमन किया था। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर को समर्पित सिक्के, डाक टिकट और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इससे पहले वर्ष 2019 में उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में डेरा बाबा से श्री करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन किया। तीर्थ यात्रियों के लिए अमृतसर से नांदेड़ तक विशेष हवाई सेवा शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हर साल 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य हमारी आस्था को सशक्त करना और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सचखंड हुजूर साहिब, नांदेड़ सिख इतिहास और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां जाकर हर श्रद्धालु को दशम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं, उनके त्याग और उनके बलिदान की अनुभूति होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और मानवता की सेवा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इससे पहले गत 28 मार्च को भगवान श्री राम की जन्मभूमि, अयोध्या धाम के लिए विशेष तीर्थ ट्रेन भेजी गई थी। उसके बाद आज यह दूसरी ट्रेन श्री हजूर साहिब भेजी जा रही है।

यूएई के फुजैराह में हमले की प्रधानमंत्री मोदी ने की निंदा

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के फुजैराह पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र पर ईरान के ड्रोन हमले की निंदा की है। हमले से आग लग गई और वहां काम कर रहे तीन भारतीय नागरिक घायल हो गए। उन्होंने नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को अस्वीकार्य बताते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, ह्लसंयुक्त अरब अमीरात पर हुए हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिनमें तीन भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूरी तरह एकजुट है और संवाद एवं कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वहीं इससे पहले विदेश मंत्रालय ने भी फुजैराह पर हुए हमले में तीन भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया। भारत ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और नागरिक बुनियादी ढांचे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने पर रोक लगाने का आह्वान किया है।

सत्य और परिश्रम से ही मिलती है स्थायी सफलता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्य, करुणा और अथक परिश्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए एक संस्कृत सुभाषितम् साझा किया। उन्होंने कहा कि केवल शक्ति और बल से नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर चलकर और निरंतर प्रयास से ही स्थायी सफलता हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि सत्य और ईमानदारी के साथ प्राप्त की गई सफलता लंबे समय तक कायम रहती है और यह मन को गहरा संतोष भी देती है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत सुभाषित साझा किया, न तथा बलवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीश्वरः। यथा सत्यानृशंस्याभ्यां धर्मेणैवोद्यमेन च॥ इस सुभाषित का अर्थ है कि जो लोग विजय प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल बल और शक्ति से सफल नहीं होते। वे सत्य, करुणा (अहिंसा), धर्म (नैतिकता) और निरंतर प्रयास (उद्यम) के बल पर ही सच्ची और स्थायी जीत हासिल करते हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारत इस स्थिति से निपटने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थक है, ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध नौवहन और व्यापार की भी मांग करते हैं। भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तत्पर है।

बंगाल की प्रचण्ड जीत के बाद दिल्ली के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचे और पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां काली का आशीर्वाद लिया और इस जीत को जनता के विश्वास और बदलाव का प्रतीक बताया। उनके साथ बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेवा सहित कई नेता मौजूद रहे।

मिनी बंगाल के नाम से जाने जाने वाले चितरंजन पार्क के लोगों ने नितिन नवीन का अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने शंख की ध्वनि के बीच पूरे विधि विधान के साथ काली मां की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया।

काली बाड़ी में पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल और उन सभी राज्यों के लोगों को बधाई देते हैं, जहां चुनाव हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। नितिन नवीन ने सभी राज्यों में शांति और समृद्धि बनी रहने की कामना की।

यूआईडीएआई ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए एनएफएसयू के साथ हाथ मिलाया

सिटी दर्पण संवाददाता

नई दिल्ली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्रों में एक संरचित, पांच वर्षीय सहयोग स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है।

- यह सहयोग साइबर सुरक्षा ऑडिट, फोरेंसिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण सहित छह प्रमुख क्षेत्रों में केन्द्रित है

यह समझौता ज्ञापन सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है और भारत के डिजिटल पहचान इकोसिस्टम को आधार प्रदान करने वाले यूआईडीएआई के डिजिटल इकोसिस्टम में साइबर सुदृढ़ता को और मजबूत करने के लिए दो प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को एक साथ लाया है।

यूआईडीएआई के सीईओ श्री विवेक चंद्र वर्मा और एनएफएसयू गुजरात परिसर के निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) एस.ओ. जुनारे के बीच इस समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

इस समारोह में यूआईडीएआई के उप महानिदेशक श्री अभिषेक कुमार सिंह और दोनों पक्षों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। यह सहयोग छह रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित होगाः शैक्षणिक और व्यावसायिक विकास, सूचना सुरक्षा और प्रणाली अखंडता, फोरेंसिक अवसंरचना और प्रयोगशाला उत्कृष्टता, साइबर सुरक्षा गतिविधियों के लिए तकनीकी सहायता, तकनीकी परामर्श और अनुसंधान (जिसमें एआई, ब्लॉकचेन, डीपफेक डिटेक्शन और क्रिप्टोग्राफिक प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान शामिल है) तथा रणनीतिक प्लेसमेंट और आउटरीच, जिसमें एनएफएसयू के छात्रों के लिए प्लेसमेंट और आउटरीच के अवसर शामिल हैं।

यूआईडीएआई के सीईओ श्री विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का समर्थन करने वाली सुरक्षा, सुदृढ़ता और फोरेंसिक क्षमताओं को और मजबूत करने तथा भारत की डिजिटल पहचान प्रणालियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रहे, देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा : योगी

सिटी दर्पण संवाददाता

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इन स्थितियों में नींव के पत्थर के रूप में बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होगी। आप जितनी मजबूत नींव खड़ी करेंगे, उतना ही सशक्त भवन बनेगा। विगत 09 वर्षां में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है।

मुख्यमंत्री जी आज जनपद गोरखपुर में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त 01 लाख 43 हजार शिक्षामित्रों की मानदेय बढ़ोत्तरी (10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये प्रतिमाह) के उपलक्ष्य में आयोजित शिक्षामित्र सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने चयनित शिक्षामित्रों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री जी ने विद्यार्थी नेतृत्व आधिरित प्रार्थना सभा गतिविधि कैलेण्डर अरुणोदय का विमोचन तथा छात्र-छात्राओं द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है। यदि शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति सकारात्मक सोच नहीं रखेगा, तो वह समाज के पुण्य की क्षति कर देगा। जिन बच्चों को अभिभावक बड़े विश्वास के साथ आपके पास विद्या अध्ययन के लिए भेज रहे हैं, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए उन बच्चों का भविष्य बनाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे, तो

बच्चे की नींव कमजोर हो जाएगी। जो व्यक्ति जितना अधिक सकारात्मक होगा, उतना अच्छा परिणाम देगा। जो जितना नकारात्मक होगा, उतना ही विध्वंसात्मक हो जाएगा तथा देश व समाज के लिए खतरनाक होगा।

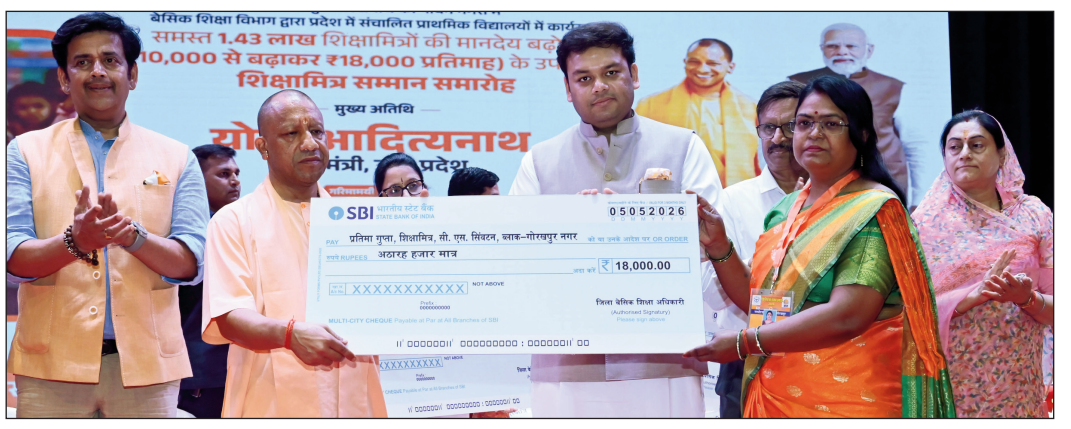

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले हमारा देश है, तब हम हैं। यह भाव हम सबको संरक्षित व सुरक्षित करेगा। अच्छी पीढ़ी तैयार करेंगे, तो प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे कार्य होंगे। समाज को बेहतर शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी, कारीगर, उद्यमी, किसान, नौकरशाह, पुलिस और राजनेता मिलेंगे। जैसा पौधा रोपेंगे, वह उसी रूप में फल प्रदान करेगा। आपको सकारात्मक भाव से आगे बढ़ने तथा बेहतर परिणाम को देने की आवश्यकता है। हमें ट्रेड यूनियन की प्रवृत्ति से दूर रहना होगा। यह भाव समाज का नुकसान करता है। अतीत में इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। देश की कीमत पर कोई भी मांग पूरी नहीं की जा सकती है।

पिछली सरकारों के मनमाने रवैया के चलते डेढ़ लाख शिक्षामित्रों के परिवारों के सामने गम्भीर आर्थिक संकट आ गया था। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे इन शिक्षामित्रों की सेवा समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था। प्रदेश सरकार ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न कर, इनका सहयोग लेंगे। वर्ष 2017 में उनका मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के 01 लाख 43 हजार शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाकर विगत अप्रैल माह से 18 हजार रुपये कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को 05 लाख रुपये वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य कवर देने की व्यवस्था की है। बहुत शीघ्र एक समारोह का आयोजन कर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्यवाही आगे बढ़ानी चाहिए।

बेसिक शिक्षा परिषद प्रयास करे कि शिक्षामित्रों के मानदेय की धनराशि किसी बैंक के माध्यम से उनके खाते में जाए, जिससे बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी प्रदान कर सकेगा। किसी भी शिक्षामित्र के साथ कोई दुर्घटना होती है, तो बैंक उनको निर्धारित बीमा कवर उपलब्ध कराएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शिक्षामित्रों की तैनाती उनके जिले में नजदीक के विद्यालय में मिले। जो शादीशुदा महिलाएं पहले अपने मायके में शिक्षामित्र के पद पर भर्ती हुई थीं, बाद में उनका विवाह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय मिले। म्युचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था पर तत्काल निर्णय लेकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा दरें बढ़ाने की मांग, सरकार ने दिया भरोसा

कांगड़ा की अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए 'गेमचेंजर' होगी एरोसिटी

जनता के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकताः सीएम सुक्खू

एजेंसी (हि.स.)
शिमला/धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार और प्रस्तावित 'एरोसिटी' परियोजना को लेकर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को शिमला में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान उप-मुख्य सचेतक एवं स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की।

इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों के लिए मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी और उनके पुनर्वास की मांग रहा। 24 लाख प्रति कनाल को नाकाफी बताया बैठक के दौरान केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिला प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा किए गए वर्तमान मूल्यांकन की रिपोर्ट रखी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में हवाई अड्डे के आसपास की बेशकीमती जमीनों का मूल्य करीब 24 लाख रुपये प्रति कनाल आंका जा रहा है। पठानिया ने पुरजोर शब्दों में कहा कि यह दर बाजार मूल्य के मुकाबले काफी कम है। भूमि अधिग्रहण की दरों का दोबारा निर्धारण किया जाए ताकि किसानों और बागवानों को उनकी आजीविका छिनने के बदले उचित मूल्य मिल सके। पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए ताकि किसी भी स्तर पर विस्थापित होने वाले परिवारों के साथ अन्याय न हो। जिन परिवारों के घर और व्यवसाय इस परियोजना की जद में आ रहे हैं, उन्हें केवल जमीन का दाम ही नहीं, बल्कि पुनर्वास के लिए अतिरिक्त सहायता भी दी जानी चाहिए। गग्गल हवाई अड्डे का विस्तार मुख्यमंत्री सुक्खू के 'कांगड़ा को पर्यटन राजधानी' बनाने के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैठक में इस परियोजना के दूरगामी आर्थिक लाभों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। बड़े विमानों की लैंडिंग संभव होने से देश-दुनिया के पर्यटक सीधे कांगड़ा पहुंच सकेंगे, जिससे होटल और होमस्टे उद्योग को भारी लाभ होगा। एरोसिटी में विकसित होने वाले कमर्शियल हब, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और लॉजिस्टिक्स सेंटर्स से स्थानीय युवाओं के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। इस परियोजना के साथ ही क्षेत्र में सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था में विश्वस्तरीय सुधार होगा, जिसका लाभ पूरे जिले को मिलेगा। विधायक पठानिया की मांगों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास के पक्ष में है, लेकिन यह विकास आम जनता की कीमत पर नहीं होगा। हमारी सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजे की दरें तर्कसंगत हों और विस्थापितों को बेहतर भविष्य के विकल्प मिलें। जिला प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे कि वे प्रभावितों की आपत्तियों को ध्यानपूर्वक सुनें। गग्गल एयरपोर्ट विस्तार के तहत लगभग 2500 कनाल अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इस विस्तार से हवाई पट्टी की लंबाई बढ़ने की उम्मीद है, जिससे बोइंग जैसे बड़े विमान यहां उतर सकेंगे। हालांकि, मांझी और मनूणी खड्डों के डायवर्जन और बड़ी संख्या में परिवारों के विस्थापन के कारण स्थानीय स्तर पर विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं।

देवऋषि नारद पहले संचारक, पत्रकारिता में संतुलन और जिम्मेदारी जरूरी: प्रताप समयाल

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख प्रताप समयाल ने कहा है कि नारद मुनि पौराणिक पात्र नहीं थे, वे तीनों लोकों में संवाद स्थापित करने वाले पहले संचारक थे। उन्होंने उन्हें ग्लोबल कम्युनिकेटर बताते हुए कहा कि उनकी संवाद शैली समावेशी, संतुलित और लोकहित पर आधारित थी।

यह बातें उन्होंने विश्व संवाद केंद्र शिमला द्वारा मंगलवार को आयोजित देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम में कहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजीव शर्मा, अध्यक्ष राज कुमार वर्मा और मुख्य वक्ता प्रताप समयाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा देवर्षि नारद और मां सरस्वती के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। कार्यक्रम में पत्रकारों, संपादकों, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स ने भाग लिया। प्रताप समयाल ने कहा कि आज के तकनीकी युग में संपर्क तो बढ़ा है, लेकिन मानवीय जुड़ाव कम हुआ है, ऐसे में पत्रकारों को नारद से प्रेरणा लेकर समाज को जोड़ने वाली पत्रकारिता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 मई 1826 को उदंत मार्तण्ड का प्रकाशन नारद जयंती के दिन हुआ था और तभी से यह दिन पत्रकारिता से भी जुड़ गया।

उन्होंने पत्रकारिता में सकारात्मकता, सच्चाई और सामाजिक जिम्मेदारी को जरूरी बताते हुए पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, पारिवारिक मूल्यों, स्व-बोध और कर्तव्य पालन जैसे पांच संकल्पों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता का काम केवल खबर देना नहीं, बल्कि समाज को दिशा देना भी है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संजीव शर्मा ने कहा कि प्रसार भारती और पीआईबी जैसी संस्थाएं सूचना तंत्र में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि खबरों को सबसे पहले दिखाने की होड़ में कई बार जल्दबाजी होती है, जिससे विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि सूचनाएं तथ्य आधारित और संतुलित हों। उन्होंने कहा कि समाचारों को सबसे पहले प्रस्तुत करने, सनसनी फैलाने और टीआरपी बटोरने की होड़ में कई बार उन्हें जल्दबाजी में प्रसारित कर दिया जाता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर भी संदेह होने लगता है। ऐसी स्थिति में नारद जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज कुमार वर्मा ने कहा कि हर समस्या के समाधान के लिए सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। समाज के लोगों को खुद आगे आकर समस्याओं को सुलझाने के प्रयास करने चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता से भी अपील की कि वह सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा दे और समाज में रचनात्मक सोच विकसित करे। इस अवसर पर आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार प्रमुख रितेश कपूर, दूरदर्शन शिमला की क्षेत्रीय समाचार प्रमुख नंदिनी मित्तल, प्रकाश पंत, प्रो. नरेन्द्र शारदा, प्रो. अजय श्रीवास्तव, डॉ. शशिकांत, वरिष्ठ पत्रकार राकेश लोहमी, अनिल हैडली और सुनील शुक्ला सहित प्रदेश के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े कई पत्रकार और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

हिमाचल पुलिस का वॉच एंड पेट्रोल मॉडल शिमला के बाद मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज में लागू

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश पुलिस की वॉच एंड पेट्रोल पहल अब राज्य के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक विस्तार की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल पहले शिमला के मॉल रोड पर लागू की गई थी, जहां इसे लोगों और पर्यटकों से अच्छा प्रतिसाद मिला। अब इस मॉडल को मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज जैसे पर्यटन स्थलों पर भी लागू किया जा रहा है।

पुलिस मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इस पहल के तहत पुलिस जवानों को औपचारिक वर्दी में प्रमुख स्थानों पर तैनात किया जाता है। उनकी भूमिका केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, वे पर्यटकों की सहायता करने, उन्हें सही दिशा बताने और जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। पुलिस का यह दोस्ताना और सहयोगी रवैया लोगों में भरोसा बढ़ाने में मदद कर रहा है। प्रवक्ता के मुताबिक मॉल रोड, शिमला में इस व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। यहां आने वाले पर्यटकों ने पुलिस की तत्परता और व्यवहार की सराहना की है, जिससे उनके बीच सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। इसी अनुभव को देखते हुए पुलिस विभाग ने इसे अन्य पर्यटन स्थलों तक विस्तार देने का फैसला किया है। राज्य के डीजीपी अशोक तिवारी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को एक सुरक्षित और पर्यटक-मित्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। साथ ही, यह प्रयास पुलिस की छवि को एक मददगार और भरोसेमंद संस्था के रूप में मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने स्वास्थ्य शिक्षक भर्ती घोटाले का भंडाफोड़ किया, आरोपी गिरफ्तार

श्रीनगर।आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) कश्मीर ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग में भर्ती धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश किया और फर्जी नियुक्तियों को सुविधाजनक बनाने में कथित भूमिका के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया। एक प्रवक्ता ने कहा कि अपराध शाखा जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू कश्मीर) कश्मीर ने पुलिस स्टेशन अपराध शाखा कश्मीर (अब ईओडब्ल्यू कश्मीर) में धारा 420, 467, 468 और 471 आरपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 19/2017 के संबंध में तलाशी ली है और एक आदतन अपराधी अहमद मीर, स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ सहायक, टैंकीपोरा शहीद गंज श्रीनगर के निवासी को इसमें शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि यह मामला उप निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर से प्राप्त एक संचार से उत्पन्न हुआ है जिसमें दर्शाया गया है कि मजहामा बडगाम के एक बशीर अहमद ने जाली स्थानांतरण आदेश और एक मनगढ़ंत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र पेश करके धोखाधड़ी से स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति हासिल की थी। जांच से पता चला कि आरोपी ने अवैध रूप से ब्लॉक शीरी बारामूला में सेवा में प्रवेश किया और वेतन उठाया जिससे राज्य के खजाने को गलत नुकसान हुआ।

अभाविप ने बढ़ते नशा, कानून-व्यवस्था और शिक्षा पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से मुलाकात कर उन्हें पदभार संभालने पर शुभकामनाएं दीं और प्रदेश की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। परिषद ने राज्य में नशे की बढ़ती समस्या, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए इन मुद्दों पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में अभाविप के कई पदाधिकारी शामिल रहे, जिनमें विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर प्रदीप कुमार, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार, प्रदेश मंत्री नैंसी अटल, प्रदेश संगठन मंत्री धनदेव ठाकुर, प्रदेश सह मंत्री भवानी ठाकुर और आरटीई प्रदेश संयोजक अमन अदिति शामिल थे। परिषद ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पीजीटी के अस्थायी पदों पर की गई नियुक्तियों को रद्द किया जाए और नियमित प्रक्रिया के तहत स्थायी भर्ती की जाए, ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर हो सके। अभाविप ने नशे के बढ़ते मामलों पर भी गंभीर चिंता जताई और कहा कि चिट्टा जैसे मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी रोक लगाई जानी चाहिए। परिषद ने मांग की कि नशा माफिया के खिलाफ सख्त कानून लागू किए जाएं, इसमें शामिल सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई हो, सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए और नशा रोकथाम बोर्ड को मजबूत किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में परिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में पूरी तरह लागू करने की मांग की। साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के खाली पदों को जल्द भरने और नियुक्तियां स्थायी आधार पर करने की बात कही। इसके अलावा अभाविप ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। परिषद का कहना है कि हत्या, दुष्कर्म, चोरी, सड़क अपराध, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध तथा साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

संक्षिप्त-समाचार

आर.एस.पुरा में दिनदहाड़े दुकानदार पर हमला कर की लूटपाट

जम्मू। जम्मू जिले के आर.एस.पुरा के वार्ड नंबर 3 में दिनदहाड़े एक दुकानदार पर हमला कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।पीड़ित दुकानदार अश्विनी गुप्ता पुत्र फकीर चंद, निवासी वार्ड नंबर 3 जरनल स्टोर चलाते हैं। अश्विनी ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे मोहल्ले का ही युवक नरेश कुमार उसकी दुकान पर आया। आरोपी कथित रूप से नशे की हालत में था। दुकान पर पहुंचते ही उसने तेजधार हथियार (टोका) निकालकर पैसों की मांग शुरू कर दी।दुकानदार द्वारा विरोध करने पर आरोपी ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसे पैर और गले पर चोटें आईं। हमलावर लगातार पैसे देने का दबाव बनाता रहा जिसके चलते पीड़ित ने अपनी कमीज की जेब में रखे करीब 6000 रुपये उसे दे दिए।घटना के दौरान दुकानदार द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गया। बाद में जानकारी मिलते ही परिजनों ने आरोपी को कुल्लियां पीर बाबा इलाके से पकड़ लिया और उसे आर.एस.पुरा पुलिस के हवाले कर दिया।पीड़ित दुकानदार ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

शादी से पहले प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन

ऊना। उपमंडल अंब के तहत एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब शादी की खुशियां अचानक मातम जैसे माहौल में बदल गईं। घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं और बटने(हल्दी) की रस्म अदा की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान दूल्हे की होने वाली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई।प्राप्त जानकारी के अनुसार, लड़के वालों के घर में रिश्तेदारों और गांव के लोगों की मौजूदगी में पारंपरिक रस्में निभाई जा रही थीं। माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था और शादी को लेकर सभी बेहद उत्साहित थे। इसी बीच अचानक दुल्हन के फरार होने की खबर सामने आई, जिससे पूरे परिवार में अफरा-तफरी मच गई और समारोह बीच में ही रोकना पड़ा।बताया जा रहा है कि युवती का पहले से ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी तय होने के बावजूद दोनों संपर्क में थे और मौका मिलते ही युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई। घटना के बाद दूल्हे पक्ष के लोग स्तब्ध रह गए और परिवार को भारी सामाजिक व मानसिक आघात पहुंचा है।इस घटना के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। गांव में भी इस मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं, लड़की के परिजनों का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी भी स्थिति की पहले से कोई जानकारी नहीं थी।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, लड़की के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।डीएसपी अनिल पटियाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर संदेह के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सभी पुलिस थानों को सूचित कर दिया गया है और जल्द ही दोनों को ढूंढ लिया जाएगा।

मंडी में सड़क हादसे में तीन की मौत, दो घायल

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बल्ह थाना क्षेत्र के तहत आने वाले डडौर में बीती रात को एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मृत्यु हो गई है जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये सभी लोग ड्राइवर बताए जा रहे हैं जो अपने किसी मित्र का हाल जानने अस्पताल जा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार यह सभी पहले मेडिकल कॉलेज नेरचौक गए जहां उन्हें अपना साथी नहीं मिला। इन्होंने सोचा कि वह सुंदरनगर में उपचाराधीन होगा। इसलिए वे यहां से सुंदरनगर की तरफ रवाना हो गए। डडौर के पास इनकी कार (HP 82 8322) सड़क किनारे खड़े हाइड्रा से टकरा गई। इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अनिल कुमार(28) निवासी पलाही, रोहित कुमार (26) निवासी अंद्रेटा और सुभाष कुमार(35) निवासी पलाही के रूप में हुई है। जबकि घायलों में हरीश(23) उर्फ सन्नी निवासी वडमाह और पंकज कुमार निवासी पलाही को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर रैफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। वहीं, मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिए गए हैं। एसपी मंडी विनोद कुमार ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच पड़ताल की जा रही है।

खिलाड़ियों पर चला प्रशासन का चाबुक, इंडोर में खेलने की फीस 150 से बढ़ाकर 1000 की

ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना में खेल के मैदान अब बच्चों के लिए पहले जैसे आसान नहीं रहे। जिन इंडोर स्टेडियमों से कभी उभरते खिलाड़ियों के सपनों को उड़ान मिलती थी, वहीं अब बढ़ी हुई फीस ने कई परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। खेल के प्रति उत्साह और भविष्य में मेडल जीतने के सपनों के बीच अब आर्थिक बाधा खड़ी होती नजर आ रही है। देश में जब भी ओलंपिक या अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात होती है, तो हर कोई चाहता है कि हमारे खिलाड़ी पदक जीतकर देश का नाम रोशन करें। लेकिन इन बड़े सपनों की नींव छोटे शहरों और कस्बों के उन्हीं मैदानों पर रखी जाती है, जहां बच्चे अपने खेल की शुरुआत करते हैं। ऊना का इंडोर स्टेडियम भी लंबे समय से ऐसे ही खिलाड़ियों की पौध तैयार करने का केंद्र रहा है। हालांकि अब यहां खेलना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। हाल ही में इंडोर स्टेडियम की फीस में तीन गुणा बढ़ोतरी की गई है। स्कूली बच्चों के लिए 150 रुपए की फीस अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है, जबकि बाहरी को 450 की जगह 1000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस बदलाव ने खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को प्रभावित किया है। जिन बच्चों के लिए यह स्टेडियम रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा था, उनके लिए अब यहां नियमित अभ्यास करना चुनौती बनता जा रहा है।

सोलन में पानी, कूड़ा और रोजगार के मुद्दों पर कांग्रेस पर बरसे डॉ. राजीव बिंदल

एजेंसी (हि.स.)
सोलन

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मंगलवार को सोलन में नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्व नगर निगम केवल आंतरिक कलह में उलझी रही, जबकि जनता मूलभूत समस्याओं से जूझती रही।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मुफ्त पानी देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह रही कि कई क्षेत्रों में 14 से 15 दिनों तक पानी की सप्लाई बाधित रही। इसके बावजूद लोगों को हजारों रुपये के बिल भरने पड़े और मजबूर होकर टैंकरों से पानी खरीदना पड़ा। उन्होंने इसे कांग्रेस की गारंटी नहीं, बल्कि जनता के साथ खुला धोखा बताया। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और कांग्रेस सरकार व नगर निगम दोनों को हटाना समय की मांग बन गया है। बिंदल के अनुसार, कांग्रेस ने चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को निराश किया। कूड़ा प्रबंधन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कूड़ा शुल्क न लेने का वादा किया था, लेकिन न केवल शुल्क लगाया गया बल्कि कई गुना बढ़ाकर वसूला गया, जबकि सफाई व्यवस्था बदहाल रही। उन्होंने हाउस टैक्स बढ़ाने का भी आरोप लगाया और कहा कि इसके बावजूद लोगों को कोई राहत नहीं मिली। महिलाओं से किए गए वादों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि 1500 प्रतिमाह देने की घोषणा के बावजूद 42 महीने बीत जाने पर भी लाखों महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिला। युवाओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी पूरा नहीं हुआ और रोजगार के अवसर घटे हैं। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि कर्मचारी, पेंशनर्स और आम जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और विरोध के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार केवल अपने करीबी लोगों के हित में काम कर रही है और आम जनता की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि देशभर में भाजपा की जीत का सिलसिला जारी है और हिमाचल प्रदेश में भी जल्द परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि सोलन नगर निगम में भाजपा की जीत तय है, जिससे विकास को नई गति मिलेगी।

मुगल रोड पर 5 लोग लापता तलाशी और बचाव अभियान जारी

पुंछ। ऐतिहासिक मुगल रोड पर एक गाड़ी में सफर कर रहे 5 लोग लापता हो गए हैं। इस सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं और जिला प्रशासन ने एक बड़ा तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने बताया कि लापता लोगों के बारे में जानकारी मिलते ही, उनकी तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गईं। यह अभियान एसडीपीओ सुरिंदर सिंह की देखरेख में चलाया जा रहा है जिसमें पुलिस, बचाव दल और स्थानीय स्वयंसेवक सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। मुगल रोड जो पुंछ को शोपियां से जोड़ता है वहां हाल के दिनों में मौसम काफी खराब रहा है जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। अधिकारियों को शक है कि खराब मौसम की वजह से गाड़ी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा हालांकि असल हालात अभी साफ नहीं हैं। तलाशी दल सड़क के पूरे इलाके की छानबीन कर रहे हैं जिसमें जोखिम भरे और बर्फ से ढके इलाके भी शामिल हैं ताकि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द और सुरक्षित बचाव सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।

किसानों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर डीसी कठुआ ने किसान खिदमत घरों की समीक्षा की

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

डीसी कठुआ राजेश शर्मा ने मंगलवार को किसान खिदमत घर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की और किसानों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया।

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि किसान खिदमत केंद्रों के माध्यम से दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को जागरूकता अभियान तेज करने के साथ-साथ फसल सलाह, मृदा परीक्षण, बीज व उर्वरक उपलब्धता, फसल बीमा और पीएम-किसान जैसी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उपायुक्त ने कहा कि किसान खिदमत घर प्रशासन और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इन्हें किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। बैठक में सीपीओ रणजीत ठाकुर, सीएओ जतिंदर खजूरिया सहित कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

दो युवकों को अफीम सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
सोलन

पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को अफीम लेकर जाते हुए धर दबोचा ।जिसमें एक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर का निवासी है तथा दूसरा आरोपी हरियाणा के जिला पंचकूला, कालका का रहने वाला है। दोनों को सोलन जिला के तहत नाकाबंदी के दौरान 4-5 मई की रात को गिरफ्तार किया गया है।

जिला सोलन के उपमंडल पुलिस दाड़लाघाट की विशेष अन्वेषण इकाई (एस आई यू टीम) द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में नाकाबंदी की गई।सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखते हुए आने-जाने वाले वाहनों की जांच आरंभ की।नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका गया। पुलिस द्वारा नियमानुसार तलाशी लेने पर दोनों व्यक्तियों के कब्जे से कुल 485 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक साईं दत्तात्रेय ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश कुमार (31) पुत्र यशपाल, निवासी गाँव सोहरी, डाकघर सिकरोहा, तहसील सदर बिलासपुर, जिला बिलासपुर तथा गौरव (29) पुत्र जितेंद्र, निवासी गुगामाड़ी मंदिर, कालका, तहसील कालका, जिला पंचकुला के रूप में हुई है।दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया क इस संबंध में पुलिस थाना अर्की में मादक द्रव्य अधिनियम के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। अन्वेषण के दौरान मामले में संलिप्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर पुलिस ने कब्जे में लिया गया है। आरोपियों को मंगलवार को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है ।इसके अतिरिक्त, गिरफ्तार आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की विस्तृत पड़ताल की जा रही है, ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि उनका किसी अन्य आपराधिक गतिविधि या नेटवर्क से कोई संबंध तो नहीं है। पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जाँच जारी है

मौसम | **10 मई से भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट**

हिमाचल में बर्फबारी, कई जगह बरसे बादल

पर्यटन और कृषि पर पड़ेगा प्रभाव

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम लगातार करवट बदल रहा है और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मई के महीने में भी बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है।मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज के साथ वर्षा दर्ज की गई। राजधानी शिमला में दिन के समय बादल बरसे, जिससे मौसम सुहावना लेकिन ठंडा बना रहा।

ऊंचाई वाले इलाकों में बादलों की घनी मौजूदगी के बीच जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के गोंदला क्षेत्र में हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई, जिससे प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी का असर भी देखने को मिला। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में यानी 6 मई को चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 6 और 7 मई को मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर बारिश जारी रहने का अनुमान है।पूर्वानुमान के मुताबिक 8 और 9 मई को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 10 मई से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 10 और 11 मई को पूरे प्रदेश में फिर से मौसम खराब रहेगा। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में वर्षा, मध्य पर्वतीय इलाकों में वर्षा और तेज हवाएं तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटों में धर्मशाला में 30.6 मिमी, कांगड़ा में 29.4 मिमी, गूलेर में 21.4 मिमी, चौपाल में 18 मिमी, शिलारू में 15.8 मिमी, सराहन में 15.5 मिमी, पालमपुर में 15.4 मिमी और मंडी में 13.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा जोगिंद्रनगर में 9 मिमी, कल्पा में 7.2 मिमी, सांगला में 6.4 मिमी और बरठीं में 5.2 मिमी बारिश हुई। बारिश-बर्फबारी से राज्य का औसतन अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है, जिससे पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द बना हुआ है तथा निचले व मैदानी इलाकों में गर्मी का असर नहीं है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 15 डिग्री, भुंतर में 11.1 डिग्री, कल्पा में 2.6 डिग्री (सबसे कम), धर्मशाला में 17 डिग्री, ऊना में 17.5 डिग्री, नाहन में 14.6 डिग्री, केलांग में 4.4 डिग्री, पालमपुर में 12.5 डिग्री, सोलन में 11.4 डिग्री, मनाली में 6.6 डिग्री, कांगड़ा में 14.6 डिग्री, मंडी में 15.4 डिग्री, बिलासपुर में 18 डिग्री, चंबा में 16.2 डिग्री, जुब्बरहट्टी में 13 डिग्री, कुफरी में 8.3 डिग्री, कुकुमसेरी में 2.9 डिग्री, सेओबाग में 8.8 डिग्री, बरठीं में 17 डिग्री, पांवटा साहिब में 21 डिग्री (सबसे अधिक) और सराहन में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया।

दैनिक सिटी दर्पण आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्क: 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

नारी के विकास से ही विकसित भारत-2047 का सपना होगा पूर्णः नायब सिंह सैनी

कहा- नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा, महिला सशक्तिकरण प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सेमिनार एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि नारी के विकास से ही विकसित भारत-2047 का सपना होगा पूर्ण होगा। जब नारी सशक्त होगी तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। कुरुक्षेत्र वह भूमि है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म और धर्म का मार्ग दिखाया। महाभारत का युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध लड़ा गया था। नारी अपमान ने समाज को यह संदेश दिया कि जब अधिकारों का हनन हो, तब मौन रहना अधर्म है। उन्होंने कहा कि आज भी समाज को इसी विचारधारा पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रश हाल में महिला सशक्तिकरण पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा ऑडिटोरियम हॉल में दीप प्रज्ज्वलित कर व वंदे मातरम गीत के बाद सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लोक सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की गई सेमिनार की स्मारिका तथा कला उत्सव की स्मारिका का विमोचन भी किया गया।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हजारों महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख आधार बताते हुए कहा कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। इसके साथ ही उन्होंने चार महत्वपूर्ण स्तंभ नारी, किसान, युवा और गरीब को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की मजबूती देश की नींव को मजबूत करती है, वहीं युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में कार्य करना जरूरी है। गरीबों को सशक्त बनाना भी राष्ट्र निर्माण की प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। एक समय था जब हमारे समाज में बेटियों को दूर पढ़ने भेजने में डर लगता था। परिवार सोचता था कि कहीं रास्ते में कोई अनहोनी न हो जाए। कई बेटियाँ सिर्फ इसी कारण अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाती थीं। लेकिन जब इस समस्या को समझा गया, तो एक पूरा रोडमैप तैयार किया गया अब हमारी सरकार द्वारा हर 20-30 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित किए गए, ताकि बेटियों को दूर न जाना पड़े और वे सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज इसका परिणाम हमारे सामने है बेटियाँ खुलकर पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और अपने सपनों को साकार कर रही हैं। अब बेटियां सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कई महिलाएं लाखों रुपये तक की आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति दोनों मजबूत हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023 में नारी शक्ति वंदन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने रानी लक्ष्मी बाई, गार्गी, मैत्रेयी और जीजाबाई जैसी महान महिलाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि नारी सदैव से शक्ति, ज्ञान और संस्कार की आधारशिला रही है। उन्होंने कहा कि आज की महिलाएं आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और

अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं और देश का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन कर रही हैं।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि एक सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। विशेष रूप से ह्यनारी शक्ति वंदन अधिनियमह्ल के संदर्भ में यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज भी महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाई है। महिलाओं के दृष्टिकोण के बिना निर्मित नीतियाँ कहीं न कहीं अधूरी रह जाती हैं। उन्होंने तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं समानता (इक्वेलिटी), न्याय संगत समानता (इक्विटी) और समावेशिता (इंक्लूसिविटी) का उल्लेख करते हुए कहा कि इक्वेलिटी का अर्थ है समान अधिकार देना, इक्विटी का अर्थ है आवश्यकता के अनुसार न्यायसंगत अवसर प्रदान करना, और इंक्लूसिविटी का अर्थ है सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना। हमारे संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है अर्थात इक्वेलिटी सुनिश्चित की गई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इक्विटी और इंक्लूसिविटी को अभी भी पूरी तरह से धरातल पर उतारना शेष है।

कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि आज आवश्यकता केवल अधिकार देने की नहीं, बल्कि वास्तविक अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करने की है। कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 55 प्रतिशत छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही है और विज्ञान संकाय में लगभग 80 प्रतिशत छात्राएँ हैं, और गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में भी 80 से 90 प्रतिशत हमारी बेटियाँ हैं। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्रतिभा और क्षमता के मामले में महिलाएँ किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी समानता, न्यायसंगत अवसर और समावेशिता पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग विशेषकर महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। आज हमारी बेटियाँ शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, रक्षा और राजनीति हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। आवश्यकता केवल उन्हें सही मंच, अवसर और प्रोत्साहन देने की है। इसी दिशा में ह्यनारी शक्ति वंदन अधिनियमह्ल एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें केवल नीतियाँ बनाने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उन्हें प्रभावी रूप से लागू करते हुए ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहाँ हर महिला स्वयं को सशक्त, सम्मानित और सक्षम महसूस करे।

कुवि दूरस्थ एवं ऑन लाइन शिक्षा केन्द्र की निदेशक प्रो. मंजूला चौधरी ने कहा कि किसी भी देश की उन्नति और समृद्धि उसके नागरिकों की शिक्षा और भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि एक महिला शिक्षित होती है, तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। यही कारण है कि महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि से देश की आय, सामाजिक गुणवत्ता और नवाचार में भी वृद्धि होती है। यदि हमें एक विकसित और सशक्त राष्ट्र बनाना है, तो सबसे पहले हमें महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, क्योंकि एक सशक्त महिला ही एक सशक्त समाज और राष्ट्र की नींव रखती है।

डीन फैकल्टी ऑफ लॉ प्रो. प्रीति जैन ने कहा कि महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। दुनिया के कई देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमसे कहीं अधिक है। भारत में यह स्थिति चिंताजनक है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। मंच का संचालन डॉ. सलोनी पवन दिवान ने किया। अंत में सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा द्वारा किया गया।

इस अवसर पर पूर्व विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक चन्द्र मोहन, कुलसचिव डॉ. वीरेन्द्र पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेन्द्र सिंह गोल्डी, जिला परिषद की अध्यक्ष कंवलजीत कौर, सरस्वती हेरीटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. राकेश कुमार, डीन आफ कालेजिज प्रो. ब्रजेश साहनी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. ए.आर. चौधरी, प्रो. अनिता दुआ, डीवीएसीए निदेशक प्रो. विवेक चावला, लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया, उप-निदेशक डॉ. जिम्मी शर्मा, डॉ. परमेश कुमार, प्रो. सुमन महेंदिया, प्रो. संगीता सैनी, प्रो. रीटा, प्रो. कुसुमलता, डॉ. आनंद कुमार, डॉ. गुरचरण सिंह, धर्मपाल चौधरी, राजवंत कौर, डॉ. शालिनी सहित शिक्षक व बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद थी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कला उत्सव प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों आराधना टंडन (पंचकूला), अंजनी रेड्डी (हैदराबाद), मीनाक्षी झा बनर्जी (दिल्ली), डॉ. कुसुमलता शर्मा (भोपाल), अनीता रघुवंशी मलिक (दिल्ली), रितु सिंह (दिल्ली), विनय कुमार शर्मा (जयपुर), के.के. गांधी, गौरई शंकर सोनी (जयपुर) तथा परदीप नायक (गोवा) को उनकी उत्कृष्ट कलाकृतियों के लिए सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को और सशक्त किया जाएगा। यहाँ महिला प्रशिक्षुओं के लिए फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी, ताकि वे नई तकनीकों में आगे बढ़ सकें और भविष्य के लिए तैयार हो सकें। कुवि में आयोजित सेमिनार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जो बेटियाँ और महिलाएँ सिविल सेवाएँ, न्यायिक सेवाएँ बैंकिंग सेवाएँ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ भी उन्हें फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी, ताकि आर्थिक कारण उनकी प्रगति में बाधा न बनें। ये केवल योजनाएं नहीं हैं ये हमारे भविष्य की नींव हैं।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोक सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार की गई स्मारिका का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसी स्मारिकाएं समाज में जागरूकता फैलाने और महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि इसमें अठारह अध्याय है जिनके अतंर्गत महिला शोध संस्थान, शोध के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिला प्रशासनिक अधिकारियों का विवरण, हॉस्टल में छात्राओं के लिए सुविधा, खेल, विज्ञान, संस्कृति, शोध प्रोजेक्ट आदि क्षेत्रों के माध्यम से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विकास में महिलाओं के योगदान को स्मारिका के अंदर शोधात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि केयू में लगभग 300 शोधार्थियों एवं अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं की क्षमता वाले हास्टल का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर लोक सम्पर्क विभाग के निदेशक प्रो. महासिंह पूनिया ने बताया कि यह महिला छात्रावास आधुनिक सुविधाओं से सम्पन्न होगा। इसमें 300 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होगी। 3 मंजिल हास्टल में कमरों के साथ अटैच बाथरूम का निर्माण किया जाएगा।

सांसद नवीन जिन्दल ने किया नवीन जिन्दल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सांसद नवीन जिन्दल द्वारा नवीन जिन्दल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया गया है। अब तक यह योजना मुख्य रूप से 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू थी, लेकिन अब विशेष परिस्थितियों में प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक के छात्र भी इसका लाभ उठा सकेंगे। अब सांसद नवीन जिन्दल द्वारा, नवीन जिन्दल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सिंगल मदर्स-विधवा महिलाओं के बच्चों और अनाथ बच्चों की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सिंगल मदर्स-विधवा महिलाओं के बच्चों की स्कूल फीस का 50 फीसदी और अनाथ बच्चों की स्कूल फीस का सौ फीसदी खर्च नवीन जिन्दल फाउंडेशन

सिंगल मदर्स-विधवा महिलाओं के बच्चों और अनाथ बच्चों की प्राइमरी से बारहवीं तक की शिक्षा के लिए किया गया विशेष प्रावधान

द्वारा वहन किया जाएगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पिछले दो वर्षों से नवीन जिन्दल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से सैकड़ों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस पहल से अनेक प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिला है। सांसद नवीन जिन्दल के निदेशानुसार अब इस योजना का विस्तार करते हुए समाज के उन वर्गों को भी शामिल किया गया है, जो विशेष परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। धर्मवीर सिंह ने आगे बताया कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने बताया कि सांसद नवीन जिन्दल का मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है, जिससे समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक छात्र या उनके अभिभावक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों तक सहायता पहुंचाई जा सके।

शहर के हर वार्ड और सैक्टर की सडकों और गलियों का किया जा रहा है निर्माण कार्यः सुभाष सुधा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- **थानेसर हलका में तीन गुणा गति के साथ करवाए जा रहे हैं विकास कार्य**
- **सुधा ने लगभग 54.95 लाख की लागत के विकास कार्यों का किया शिलान्यास**

हरियाणा के पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से थानेसर शहर के हर वार्ड और सेक्टर की खराब सडकों और गलियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस शहर में लगभग सभी प्रमुख सडकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। थानेसर हलका में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीन गुणा गति के साथ विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस हलका के गांव और शहरों में सबका साथ सबका विकास नीति को आधार मानकर विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। अहम पहलू यह है कि शहर के विकास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट की कोई कमी नहीं रख रहे। आए दिन शहर में एक के बाद एक विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के किसी भी प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ले जाने के देरी हैं, वहां से परियोजना को मंजूरी साथ के साथ मिल रही है।

पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा नगरपरिषद थानेसर में वार्ड नंबर 1 में 13.46 लाख की लागत से विभिन्न स्थानों पर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का निर्माण और मरम्मत का शिल्यान्यास किया। इसके अलावा लगभग 41.49 लाख रुपए की लागत से आरसीएनपी3 पाइप 600 डीआईए रेलवे रोड से अमीन रोड तक हनुमान मंदिर होते हुए वार्ड नंबर 19 नगरपरिषद थानेसर का शिल्यान्यास किया।

हरियाणा की फायर सर्विस को 400 करोड़ रुपये खर्च करके किया जाएगा आधुनिक : डॉ. मिश्रा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा की फायर सर्विस का 400 करोड़ रुपये खर्च करके आधुनिकीकरण किया जाएगा।

डॉ. मिश्रा आज यहां सेक्टर-26 स्थित इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के 54वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने संस्था द्वारा 150 से अधिक दिव्यांग बच्चों, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां शामिल हैं, को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने समाज में सहयोगात्मक सोच के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल एक नेक सेवा है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी है। डॉ. सुमिता मिश्रा ने आगामी मानसून और गर्मी के मौसम के लिए राज्य की तैयारियों के साथ-साथ जल्द लागू होने वाले प्रमुख प्रशासनिक सुधारों की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आपदा प्रबंधन की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि हरियाणा 14 मई को 13 संवेदनशील जिलों में राज्य स्तरीय, बहु-चरणीय बाढ़ मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ठउटअ) के समन्वय से 2026ह्र27 के वार्षिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश मॉक एक्सरसाइज कैलेंडर के तहत किया जाएगा। यह अभ्यास तीन चरणों में होगा—पहला चरण 6 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओरिएंटेशन एवं समन्वय बैठक, दूसरा चरण 12 मई को टेबल-टॉप एक्सरसाइज, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, संचार प्रोटोकॉल और सिमुलेशन पर ध्यान दिया जाएगा, और अंतिम चरण 14 मई को जमीनी स्तर पर पूर्ण पैमाने का अभ्यास होगा, जिसमें सभी एजेंसियां, अग्रिम पंक्ति के कर्मी और आम जनता भाग लेगी। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत, पलवल, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर जिलों को नदियों और नहरों की निकटता तथा पूर्व में बाढ़ की संवेदनशीलता के आधार पर चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना, तैयारियों का आकलन करना और मानसून से पहले लॉजिस्टिक्स एवं प्रतिक्रिया तंत्र में कमियों की पहचान करना है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि आगामी दिनों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए सभी जिलों में व्यापक स्वास्थ्य एडवाइजरी पहले से लागू है। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों—अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों—को ओआरएस, आईवी फ्लूड्स, आइस पैक और आवश्यक आपात उपकरणों का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला स्तर पर हीटस्ट्रोक प्रबंधन इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।

प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना है सरकार की प्राथमिकताः नायब सिंह सैनी

सिटी दर्पण संवाददाता
लाडवा

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए दो गौ अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है। एक जिला पानीपत के गांव नैन और दूसरा जिला हिसार के गांव ढंढुर में बनाया गया है। इनमें शैड, पानी, चारे की व्यवस्था की गई है। इनके लिए 8 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 51 गौशालाओं को शैड बनाने के लिए 10 लाख रुपये प्रति गौशाला अनुदान देने का प्रावधान किया है। इनमें से 21 गौशालाओं में शैड बनाने हेतु अनुदान दिया जा चुका है। इसी तरह पंचगव्य आधारित उत्पादों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौवंश अनुसंधान केंद्र सुखदर्शनपुर पंचकूला की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को कुरुक्षेत्र के लाडवा में श्री कृष्ण गौशाला सोसायटी में गौशाला चारा अनुदान राशि वितरण समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद उपाध्यक्षा श्रीमती सुमन सैनी के साथ गौशाला में गौ पूजा की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाडवा व थानेसर हल्के की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70 लाख 24 हजार रुपये की चारा अनुदान राशि के चैक वितरित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं के लिए चारा अनुदान राशि वितरण समारोह हमारी संस्कृति, हमारी सेवा और समर्पण भावना से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आज फिर मुझे गौमाता की सेवा का अवसर मिला है। आज की 11 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 70 लाख 24 हजार रुपये की चारा अनुदान राशि को मिलाकर वर्ष 2025-26 में पूरे प्रदेश की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की जा चुकी है। पंजीकृत गौशालाओं को पिछले सवा 11 वर्षों में 526 करोड़ 45 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे वेदों और पुराणों ने गाय को समृद्धि, शांति और जीवन का आधार माना है। गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म-ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। हमारे देश में गाय आदिकाल से ही पूजनीय रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, गाय में सभी देवी-देवता निवास करते हैं। गाय

को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। हमारे ग्रंथों और वेदों में कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी। गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2026-27 के बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया है। इनमें मुस्नोता, नांगल जाट, शिव गौशाला (मतलौडा), मोर खेड़ी, बलौली, दहिमन, गौ-अभ्यारण (नैन) शामिल हैं। इसके अलावा कारी आदू, ढूंढ़वा, मोहम्मदपुर अहीर व ममरिया आसमपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में केवल 1 लाख 75 हजार गौवंश था, लेकिन इस समय राज्य में 697 पंजीकृत गौशालाएं हैं। इनमें लगभग 4 लाख से अधिक बेसहारा गौवंश का पालन-पोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत गौशालाओं में से 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। वर्ष 2026-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार गौशालाओं में 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले गौशालाओं से जमीन की रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब नई गौशालाओं को जमीन की रजिस्ट्री पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गौवंश के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमने पशुचिकित्सों की व्यवस्था की है। हमने तीन हजार से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन पशुचिकित्सक की ड्यूटी लगाने का काम किया है। इसके अलावा तीन हजार से कम गायों वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन वी.एल.डी.ए. की ड्यूटी लगाई है। इसके साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देशी नस्ल की गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी कारगर कदम उठाने होंगे। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' लागू किया है। उन्होंने कहा कि देशी नस्ल की हरयाणा, साहीवाल व बेलाही गायों के गौपालकों को दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5 हजार से 20 हजार रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सडकों पर विचरण कर रहे बेसहारा गौवंश को पकडकर अपनी गौशाला में लाने पर गौशाला को 300 रुपये प्रति बछड़ा व बछड़ी, 600 रुपये प्रति गाय तथा 800 रुपये प्रति नंदी (सांड) मानदेय देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 4 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। सरकार द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। गौशालाएं गाय के गोबर और गोमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फॉस्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर से प्राकृतिक पेंट, गमला, दीया, धूप, साबुन और अन्य उत्पाद बना रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद दी जा रही है। गाय के गोबर से डंडे, धूप बत्ती, उपले गमले की मशीन या गौ मूत्र से गौ अर्क, गोनाईल आदि बनाने की मशीनों पर 101 गौशालाओं को अनुदान राशि दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गौमाता की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा गौ-वंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम-2015 लागू किया है। इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को सात वर्ष तक की कैद का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के संचालन में समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार सहयोग कर सकती है, संसाधन दे सकती है, लेकिन सेवा और समर्पण समाज के सहयोग से ही संभव है। मैं सभी पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे अपने गांव की गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल करें।

संपादकीय

जनहित याचिका का दुरुपयोग: न्यायपालिका की चिंता और समाज की जिम्मेदारी

भारत की न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका यानी PIL को एक क्रांतिकारी अवधारणा माना जाता रहा है। इसकी नींव इसलिए रखी गई थी ताकि समाज का वह वर्ग, जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से अदालत का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है, उसे भी न्याय मिल सके। किसी भी जागरूक नागरिक को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी पीड़ित की ओर से, अथवा जनसामान्य के व्यापक हित में, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सके। यह अवधारणा भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी उपलब्धि थी। परंतु आज यही PIL एक ऐसे उपकरण में बदलती जा रही है, जिसका उपयोग जनहित के लिए नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, प्रचार की भूख और आर्थिक लाभ के लिए किया जाने लगा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक टिप्पणी की। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि अब जनहित याचिका वास्तव में निजी हित याचिका, प्रचार हित याचिका, पैसा हित याचिका और राजनीतिक हित याचिका बन गई है। यह चार 'P' वाली टिप्पणी महज एक चुटीली बात नहीं थी – यह न्यायपालिका की उस गहरी पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, जो वर्षों से PIL के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए संचित होती रही है। यह टिप्पणी सबरीमाला मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई। पीठ ने 'इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन' की उस PIL पर सवाल उठाया, जो 2006 में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के सबरीमाला मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए दाखिल की गई थी। पीठ का प्रश्न था कि आखिर इस संगठन को इस मामले में याचिका दाखिल करने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ? क्या एक समाचार लेख पढ़कर PIL दाखिल की जा सकती है? मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस PIL को तो शुरू में ही खारिज कर देना चाहिए था। यह कड़ी टिप्पणी बताती है कि न्यायालय अब ऐसी याचिकाओं के प्रति कितना सतर्क और सख्त हो गया है। PIL की अवधारणा 1970 और 1980 के दशक में भारत में उभरी, जब न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने न्यायिक सक्रियता को एक नई दिशा दी। उन्होंने यह माना कि अदालतें केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं रह सकतीं, जो महंगे वकीलों को फीस दे सकते हों। बंधुआ मजदूरों, जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों, पर्यावरण प्रदूषण से पीड़ित समुदायों और वंचित वर्गों के लिए PIL एक वरदान बनकर आई। SP गुप्ता बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने PIL की अवधारणा को विधिवत परिभाषित किया और यह स्पष्ट किया कि यह संविधान के अनुच्छेद 39A की भावना के अनुरूप शीघ्र सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है। परंतु धीरे-धीरे यह औजार एक हथियार बन गया – और वह भी गलत हाथों में। आज अदालतों में अनेक ऐसी PILs दाखिल होती हैं जिनका जनहित से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं होता। कुछ लोग इसका उपयोग अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों को परेशान करने के लिए करते हैं। कुछ राजनेता विरोधी दलों की सरकारों को घेरने के लिए PIL का सहारा लेते हैं। कुछ लोग अखबारों में अपना नाम छपवाने के लिए बड़ी-बड़ी याचिकाएं दाखिल करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं, जो मामला वापस लेने के बदले में पर्दे के पीछे समझौता कर लेते हैं। यही 'पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन' है – जिसकी ओर न्यायालय ने संकेत किया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश को प्रतिदिन सैकड़ों पत्र प्राप्त होते हैं – क्या उन सबको PIL में परिवर्तित किया जा सकता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसका उत्तर स्पष्ट है – नहीं। PIL एक असाधारण उपाय है, और इसे असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। जब हर कोई हर बात पर PIL दाखिल करने लगता है, तो न्यायालय का अमूल्य समय नष्ट होता है और वास्तविक पीड़ितों के मामले वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं। यहाँ एक मौलिक प्रश्न उठता है – क्या PIL के दुरुपयोग की जिम्मेदारी केवल याचिकाकर्ताओं की है? नहीं। इसमें कुछ हद तक न्यायालयों की उदारता भी जिम्मेदार है। दशकों तक न्यायालयों ने PIL को बहुत उदारतापूर्वक स्वीकार किया। भले इरादे से, लेकिन इस उदारता ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया, जहाँ याचिका दाखिल करना बेहद आसान और जोखिम-मुक्त हो गया। यदि याचिका खारिज भी हो जाए, तो याचिकाकर्ता को कोई बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। न्यायालय ने स्वयं यह माना है कि PIL एक असाधारण और सस्ता उपाय है, इसलिए इसे साधारण मुकदमेबाजी के विकल्प के रूप में या तुच्छ शिकायतों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। समाधान क्या हो? पहली बात यह कि PIL दाखिल करने की प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाया जाए। याचिकाकर्ता को यह बताना अनिवार्य हो कि वह किस जनहित की रक्षा के लिए यह याचिका दाखिल कर रहा है और उसका उस मामले से क्या संबंध है। दूसरी बात, फ्रिवोलस यानी तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण PILs पर भारी जुमार्ना लगाया जाए, ताकि लोग इसे खिलवाड़ न समझें। तीसरी बात, मीडिया और नागरिक समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी – हर PIL को सनसनीखेज खबर बनाने से बचना होगा, क्योंकि इससे प्रचार-भूखे याचिकाकताओं को बल मिलता है। PIL आज भी एक अत्यंत आवश्यक और मूल्यवान संस्था है। जब कोई आदिवासी समुदाय अपनी जमीन बचाने के लिए PIL दाखिल करता है, जब कोई पर्यावरणविद् नदियों के प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाता है, जब कोई अनाथ बच्चों के अधिकारों के लिए अदालत की शरण लेता है – तब PIL अपने असली स्वरूप में होती है। इसे इस असली स्वरूप में जीवित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।सर्वोच्च न्यायालय की यह चेतावनी एक आईना है – जो हमें दिखाता है कि हमने एक महान संस्था के साथ क्या किया है। अब समय आ गया है कि विधि आयोग, संसद, न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर PIL की मूल भावना को पुनर्स्थापित करें। जनहित याचिका को जनहित का ही माध्यम बने रहने दें – इसे पैसे, प्रचार, निजी स्वार्थ और राजनीति का हथियार न बनने दें। न्याय की यह मशाल तभी जलती रहेगी, जब इसे सच्ची नीयत और ईमानदार इरादे से थामा जाए।

पत्रकारिता केवल माइक या कैमरे का खेल नहीं

डॉ. प्रियंका सौरभ (हि.स)

आज डिजिटल युग में सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तेज और व्यापक हो चुका है। स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट ने हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का मंच दे दिया है। एक ओर यह लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत है, वहीं दूसरी ओर यह स्थिति कई गंभीर चुनौतियां भी लेकर आई है। विशेषकर तब, जब कुछ लोग मात्र 100झ्200 रुपये के माइक और कैमरे के सहारे स्वयं को पत्रकार घोषित कर लेते हैं और बिना किसी जिम्मेदारी के सूचनाएं प्रसारित करने लगते हैं। यह समस्या केवल व्यक्तियों की नहीं, बल्कि उस सोच की है, जो पत्रकारिता को एक जिम्मेदार सामाजिक दायित्व की बजाय व्यूज और लाइक्स के खेल में बदल देती है।

डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता को लोकतांत्रिक बनाया है। अब केवल बड़े मीडिया हाउस ही सूचना के वाहक नहीं रहे, बल्कि आम नागरिक भी घटनाओं को रिकॉर्ड कर समाज के सामने ला सकते हैं। कई बार यही नागरिक पत्रकारिता उन मुद्दों को उजागर करती है, जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया नजरअंदाज कर देता है। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए शक्ति का स्रोत भी है, क्योंकि इससे आवाजों की विविधता बढ़ती है और सत्ता के हर स्तर पर जवाबदेही की मांग मजबूत होती है। लेकिन यही खुलापन जब बिना जिम्मेदारी के इस्तेमाल होता है, तो यही ताकत कमजोरी में बदल जाती है।

आज सोशल मीडिया पर वायरल होना ही सफलता का पैमाना बन गया है। इस दौड़ में कुछ लोग विवाद, सनसनी और अधूरी जानकारी के सहारे लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि तीखी भाषा, आरोप और उत्तेजना लोगों का ध्यान खींचती है, इसलिए वे तथ्यों की बजाय भावनाओं को उकसाने पर अधिक जोर देते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि समाज में भ्रम फैलता है और सच-झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लोग बिना पुष्टि किए ही किसी भी सूचना को सच मान लेते हैं, जिससे अफवाहें तेजी से फैलती हैं और उनका प्रभाव गहरा होता जाता है।

इसका सीधा असर सरकारी संस्थाओं पर भी पड़ता है। सरकारी संस्थाएं किसी भी राष्ट्र की प्रशासनिक रीढ़ होती हैं और उनका उद्देश्य जनसेवा है। यदि उनके बारे में गलत या भ्रामक जानकारी फैलती है, तो जनता का विश्वास कमजोर होता है। यह विश्वास किसी एक खबर से नहीं, बल्कि लगातार फैलती अधूरी या भ्रामक सूचनाओं से धीरे-धीरे क्षीण होता है। परिणामस्वरूप, लोग व्यवस्था पर संदेह करने लगते हैं, जो अनावश्यक टकराव और असंतोष को जन्म दे सकता है। यह भी उतना ही सच है कि सरकारी संस्थाएँ त्रुटिहीन नहीं हैं, लेकिन उनकी कमियों को उजागर करने का तरीका तथ्यपूर्ण और जिम्मेदार होना चाहिए, न कि केवल सनसनी के लिए।

हर छोटे माइक वाले व्यक्ति को नकली पत्रकार कहना भी उतना ही गलत है, जितना हर वायरल खबर को सच मान लेना। पत्रकारिता का मूल्य उपकरणों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण, ईमानदारी और जिम्मेदारी से तय होता है। कई बार छोटे और स्वतंत्र पत्रकार ही जमीनी सच्चाई सामने लाते हैं, जबकि बड़े संस्थान भी कभी-कभी दबावों में चूक कर बैठते हैं। इसलिए समस्या को 'छोटे बनाम बड़े' के रूप में देखने के बजाय 'जिम्मेदार बनाम गैर-जिम्मेदार' के रूप में समझना अधिक उचित है। असली संकट पत्रकारिता के मूल्यों में गिरावट का है, जहाँ नैतिकता और तथ्य-जांच की जगह जल्दबाजी और लोकप्रियता ने ले ली है।

समाधान किसी एक कदम में नहीं छिपा है, यह सामूहिक प्रयास से ही संभव है। सबसे पहले समाज को मीडिया साक्षर बनना होगा, ताकि लोग हर सूचना को बिना जांचे-परखे स्वीकार न करें। उन्हें समझना होगा कि किसी खबर की विश्वसनीयता उसके स्रोत, प्रमाण और संदर्भ से तय होती है, न कि उसके वायरल होने से। साथ ही, फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई भी जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ अराजकता नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और भ्रामक कंटेंट पर नियंत्रण के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रशिक्षण और नैतिक मानकों की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जा रही है। पत्रकार बनने के लिए औपचारिक डिग्री अनिवार्य नहीं हो सकती, लेकिन बुनियादी समझ, तथ्य-जांच की प्रक्रिया और समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध होना आवश्यक है। इसके साथ ही, जो लोग ईमानदारी और संतुलन के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि सकारात्मक उदाहरण स्थापित हो सकें।

आज की सबसे बड़ी आवश्यकता संतुलन की है। न तो हर छोटे पत्रकार को खारिज करना उचित है, और न ही हर खबर पर आंख मूंदकर विश्वास करना। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सूचना का यह नया युग अवसर और खतरे दोनों लेकर आया है। इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसे सही दिशा जरूर दी जा सकती है– और यह दिशा तभी संभव है जब समाज, मीडिया और शासन तीनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को समझें।

अंततः पत्रकारिता केवल माइक या कैमरे का खेल नहीं है, बल्कि यह सत्य के प्रति प्रतिबद्धता है। यदि यह प्रतिबद्धता कमजोर पड़ती है, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित होती है। सरकारी संस्थाओं की आलोचना जरूरी है, लेकिन वह तथ्य और संतुलन पर आधारित होनी चाहिए। वहीं, समाज को भी यह समझना होगा कि हर आवाज को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता। असली संघर्ष 'नकली बनाम असली' का नहीं, बल्कि 'सत्य बनाम सनसनी' का है–और इस संघर्ष में वही आगे बढ़ेगा, जो जिम्मेदारी, ईमानदारी और विवेक को अपना आधार बनाएगा।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। नौकरी से जुड़े मामलों में उत्साह बना रहेगा। अपनी निजी बातें किसी से साझा करते समय सावधानी बरतें। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: व्यापार में बड़े निवेश से फिलहाल दूरी बनाए रखें। जीवनसाथी के साथ संबंधों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। बढ़ते खर्च मानसिक असंतोष का कारण बन सकते हैं, हालांकि समय आपके पक्ष में रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: जीवनसाथी का सहयोग और समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे रिश्तों में मिठास आएगी। रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और रिश्तों के प्रति भावनात्मक रहेंगे। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आज अपने काम पर पूरी एकाग्रता बनाए रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में कोई वादा न करें। ऑफिस में राजनीति से दूरी बनाए रखें। घर में अचानक मेहमान आ सकते हैं। कटु वाणी से बचें और खानपान में संतुलन बनाए रखें। *(सिटी दर्पण)*

सिंह: आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आत्मविश्लेषण की जरूरत है। प्रेम संबंधों में शक की भावना से बचें। आपके सुझाव दूसरों के लिए लाभदायक साबित होंगे। घर में खुशी का माहौल रहेगा और किसी रिश्तेदार के यहां समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: आज अधिकांश कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। आप सुख-सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। जरूरी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। शाम के समय जीवनसाथी के साथ हल्की नोकझोंक हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

तुला: वैवाहिक जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। आपके व्यवहार में कठोरता के कारण कुछ करीबी नाराज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। लोग आपके काम से प्रभावित रहेंगे और इंटरनेट के माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। *(सिटी दर्पण)*

वृश्चिक: दिन की शुरूआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी। दोपहर के बाद व्यस्तता बढ़ सकती है, इसलिए जरूरी कार्य सुबह ही निपटा लें। आप अपने अधिकारों का प्रभावी उपयोग करेंगे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सकता। *(सिटी दर्पण)*

धनु: आर्थिक मामलों में असंतोष रह सकता है। करीबी लोगों के व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है। शाम को धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मौसमी बीमारियों से सावधान रहें। गलतियों को सुधारने का प्रयास करें और पुराने कर्ज चुकाने का दबाव महसूस हो सकता है। *(सिटी दर्पण)*

मकर: समस्याएं जीवनसाथी के साथ साझा करना लाभकारी रहेगा। आप प्रकृति के बीच समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। कार्य के दौरान शांत रहना बेहतर होगा। कार्यक्षेत्र में धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन सहकर्मियों के व्यवहार को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: नई योजनाओं को लेकर उत्साह रहेगा। जीवनसाथी भावनाओं को समझेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशहाल माहौल बना रहेगा। परिस्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में आप भावुक रह सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

मीन: काम का दबाव कम होने से राहत मिलेगी। नया घर खरीदने या निर्माण की योजना बन सकती है। कोई शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। व्यापार में धीरे-धीरे सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करेंगे। *(सिटी दर्पण)*

बदलते बंगाल की नई इबारत: वाम से ममता और अब भाजपा!

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से विचारधाराओं, आंदोलनों और सत्ता संघर्षों की प्रयोगशाला रही है। 1977 से 2011 तक वामपंथ का लंबा शासन, उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का उदय और अब 2026 में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत- ये तीनों चरण वास्तव में इस राज्य के लिए जनमानस के बदलते विश्वास का प्रतिबिंब हैं।

1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चा सत्ता में आया और अगले 34 वर्षों तक उसने राज्य की राजनीति पर एकछत्र राज किया। शुरूआती वर्षों में भूमि सुधार और पंचायत सशक्तिकरण जैसे कदमों ने ग्रामीण समाज को नई दिशा दी, लेकिन समय के साथ यही शासन तंत्र जड़ता का शिकार हो गया। सत्ता का केंद्रीकरण, राजनीतिक हिंसा और औद्योगिक विकास की कमी, हिन्दू अत्याचार, मुस्लिम तुष्टिकरण से जैसे राज्य की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक गति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था।

नंदीग्राम और सिंगूर: बदलाव की चेतना

2007 के नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों ने वामपंथी शासन की नींव को हिला दिया। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ उठे इन जनआंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जनता अब विकास के नाम पर जबरदस्ती स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इन घटनाओं ने जनता के भीतर परिवर्तन की इच्छा को मजबूत किया।

ममता बनर्जी का उदय और उम्मीदों का नया दौर

2011 में ममता बनर्जी ने 'मां, माटी, मानुष' के नारे के साथ सत्ता संभाली। ममता बनर्जी ने खुद को गरीबों, किसानों और आम लोगों की नेता के रूप में स्थापित किया। शुरूआती वर्षों में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी और लगा कि बंगाल एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता चला, लोगों के ध्यान में आया कि ममता बनर्जी भी उसी राह पर चल पड़ी हैं, जिसके चलते वामपंथी शासन का किला यहां की जनता ने ढहाया था। समय के साथ ममता

सरकार पर भी वही आरोप लगने लगे जो कभी वामपंथ पर लगते थे। 'कट मनी', राहत घोटाले और प्रशासनिक पक्षपात जैसे मुद्दों ने सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर किया। स्थानीय स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का बढ़ता प्रभाव और प्रशासन पर राजनीतिक दबाव ने शासन की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए।

राजनीतिक हिंसा: एक स्थायी चुनौती

पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा एक गंभीर समस्या रही है। 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा ने पूरे देश का ध्यान खींचा। आरोप लगे कि विपक्षी कार्यकर्ताओं विशेष तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों को निशाना बनाया गया। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे और जनता के भीतर असुरक्षा की भावना बढ़ी।

महिला सुरक्षा और सामाजिक असंतोष

महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों, विशेष रूप से आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाया। जिस 'मां, माटी, मानुष' के नारे के साथ ममता बनर्जी ने सत्ता संभाली थी, ध्यान में आया कि उनके शासन में लगातार महिलाओं पर हिंसा बढ़ी है, बलात्कार के अनेक मामले एक के बाद एक यहां सामने आए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं का एक बड़ा वर्ग सरकार से निराश होता गया। यह असंतोष धीरे-धीरे राजनीतिक रूप लेने लगा और चुनावी परिणामों में आज इसका असर स्पष्ट दिखाई दिया है।

भाजपा का प्रवेश: विकल्प की तलाश का उत्तर

भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में धीरे-धीरे अपनी जड़ें मजबूत कीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जीतकर पार्टी ने यह संकेत दे दिया था कि वह अब एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी छवि ने पार्टी को विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यहां देखने में आता है कि भाजपा ने केवल चुनावी रणनीति पर ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक विस्तार पर भी जोर दिया। बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता, सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति और लगातार जनसंपर्क ने पार्टी को मजबूत आधार दिया। यह विस्तार सामाजिक स्तर पर भी प्रभावी साबित हुआ और आज भाजपा यहां निर्णायक सत्ताधारी दल के रूप में स्थापित होने जा रही है।

जनादेश का निर्णायक संदेश

अब तक के सामने आए विधानसभा चुनाव में बढ़त को देखकर लगता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। यहां हुआ 92 प्रतिशत से अधिक मतदान यह दशार्ता है कि जनता ने इस बार निर्णायक बदलाव का मन बना लिया था। जोकि शासन के प्रति जनता के असंतोष का स्पष्ट संदेश है। कहना होगा कि भाजपा की जीत आज उस व्यापक जनभावना का परिणाम है जो बदलाव चाहती थी। लोगों ने भाजपा को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखा जो स्थिरता, विकास और मजबूत शासन दे सकता है। भाजपा के सत्ता में आने से केवल सरकार नहीं बदलेगी, बल्कि राजनीतिक संस्कृति में भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है। हिंसा मुक्त चुनाव, पारदर्शी प्रशासन और विकास केंद्रित राजनीति, ये वे अपेक्षाएं हैं जो जनता भाजपा से कर रही है।

आर्थिक विकास की नई उम्मीदें

बंगाल लंबे समय से औद्योगिक विकास में पिछड़ता रहा है। भाजपा के नेतृत्व में निवेश, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से विकास को गति मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति का यह सफर दशार्ता है कि जनता हमेशा बदलाव की तलाश में रहती है। 34 वर्षों का वाम शासन, 15 वर्षों का तृणमूल शासन और अब भाजपा का उदय, आज ये सभी उस लोकतांत्रिक चेतना के प्रतीक हैं जो समय-समय पर खुद को अभिव्यक्त करती है। 2026 का जनादेश पश्चिम बंगाल के लिए एक नई दिशा की शुरूआत है, जिसमें भाजपा के नेतृत्व में बंगाल एक नए अध्याय की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है।

देश के श्रम परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका

मुकुंद (हि.स)

देश का श्रम परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इसने पुरुष और स्त्री के दायरे को खत्म कर दिया है। आज भारत की महिला श्रम के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के श्रम परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव और वृद्धि देखी गई है। अब देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे को बदलने वाली भी है।महिला श्रम बल भागीदारी दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह दर 2017-18 में 23.3 फीसद थी। 2024-25 में बढ़कर यह 41.7 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ग्रामीण भारत में भी बदलाव और वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका अग्रणी है। कृषि और पशुपालन के साथ-साथ स्वरोजगार में उनकी सक्रियता बढ़ी है। देश में आज भी कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि (लगभग 60 प्रतिशत से अधिक) और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है।

शहरी क्षेत्रों में महिलाएं आईटी, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। महानगरों में नियमित रोजगार के मामले में लैंगिक अंतर काफी कम हुआ है। 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अब सूक्ष्म उद्यमी बन रही हैं। इससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है।विडंबना यह है कि कार्यबल में शामिल होने के बावजूद महिलाएं घरेलू काम और बच्चों की देखभाल का असंगत बोझ उठाती हैं। समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में महिलाओं को मिलने वाले वेतन में अभी भी अंतर बना हुआ है। खासकर विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में यही स्थिति है।

सरकारी कोशिशों के बावजूद वरिष्ठ प्रबंधन और निर्णय लेने वाले पदों (जैसे बोर्ड मेंबर या सीईओ) पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है। सरकारी पहल और भविष्य की राह सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी

पढ़ाओ', 'मुद्रा योजना' (जिसमें 70 प्रतिशत ऋण महिलाओं को दिए गए) और मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम जैसे कदमों के जरिए महिलाओं को श्रम शक्ति में बनाए रखने का प्रयास किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार, महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से भारत की जीडीपी विकास दर में उल्लेखनीय उछाल आ सकता है।

महत्वपूर्ण यह है कि कुछ वक्त पहले तक देश में महिलाओं के ज्यादातर काम अनदेखे ही रहते थे। उनके कामों का ज्यादातर हिस्सा घरों, पारिवारिक उद्यमों और अनौपचारिक भूमिकाओं तक ही सीमित था। इनका आधिकारिक दस्तावेजों में शायद ही कभी जिक्र होता रहा हो। अब स्थिति बदल रही है और महिलाएं देश के श्रम परिदृश्य को नया रूप दे रही है। देश के कार्यबल में बदलाव की कहानी आंकड़ों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि महिला श्रम बल भागीदारी में तेजी से वृद्धि हुई है, जो 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 40 प्रतिशत हो गई है। खुशी की बात है कि इस बदलाव का नेतृत्व ग्रामीण भारत कर रहा है।

यही नहीं गांवों और छोटे कस्बों की महिलाएं अब पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर उद्यमिता की ओर अग्रसर हो रही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक महिला परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है। वित्तीय समावेशन के मार्ग के रूप में शुरू हुआ यह प्रयास धीरे-धीरे सूक्ष्म उद्यमों के एक नेटवर्क में तब्दील हो गया है। यहां महिलाएं उत्पादन, प्रबंधन और बिक्री कर रही हैं और अक्सर अपने परिवारों में प्राथमिक आय का स्रोत बन रही हैं।

महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए नए सिरे से शुरू किए गए नीतिगत प्रयासों से इस रफ्तार में और तेजी आई है। लखपति दीदी कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पहल महिलाओं को अपनी आय को स्थायी रूप से बढ़ाने में सक्षम बनाने पर केंद्रित हैं। इसका मकसद प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक कमाने वाली करोड़ों महिला उद्यमियों का सृजन करना है। ऋण, कौशल और बाजार संपर्कों तक विस्तारित पहुंच के साथ, यह भागीदारी से आय सुरक्षा की ओर एक बदलाव का प्रतीक है, जहां महिलाएं न केवल काम कर रही हैं, बल्कि अधिक मजबूत आजीविका का निर्माण भी कर रही हैं।

यह बदलाव देश के बढ़ती स्टार्टअप व्यवस्था में भी दिखाई देने लगा है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है। अच्छी बात यह है कि 2.2 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 23.3 लाख से अधिक रोजगार सृजित कर रहे हैं। इनमें से एक लाख से अधिक स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक हैं। इसके साथ ही स्किल इंडिया मिशन और अन्य सरकारी कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों की मदद से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों से जुड़े कौशल से लैस किया जा रहा है। उद्योगों पर आधारित कौशल विकास पर यह बढ़ता जोर, रोजगार क्षमता में सुधार करने और अधिक स्थिर और उत्पादक आजीविका की ओर बढ़ने में मददगार साबित हो रहा है।

हाल के श्रम सुधारों ने भी इस अंतर को दूर करने का प्रयास किया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेकित करने से नियामक ढांचा सरल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इन सुधारों के कार्यान्वयन का स्वागत करते हुए कहा, "ये संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी का भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और लोगों, विशेष रूप से नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों की मजबूत नींव के रूप में कार्य करेंगी।" व्यापक स्तर पर पर देखा जाए तो, देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में करीब 19 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 64 प्रतिशत से अधिक हो गया है। सुखद यह है कि इस परिदृश्य में महिलाएं न केवल कार्यबल का हिस्सा हैं, बल्कि भविष्य को आकार देने में भी वे केंद्रीय भूमिका निभा रही हैं।

मैंने राष्ट्रपति भवन में पंजाब के सभी विधायकों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपा है और राष्ट्रपति से कार्रवाई की अपील की : भगवंत सिंह मान

सिटी दर्पण संवाददाता
नई दिल्ली/पंजाब

आप विधायकों को लेकर दिल्ली राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे भगवंत मान ने जोर देकर कहा, पंजाबी इस तरह पीठ में छुरा मारना बर्दाश्त नहीं करते और उन्हें प्रदेश के लोग सजा देंगे। ये नेता अब उलझे हुए हैं, जिसके कारण वे बेतुके बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, भाजपा में शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि इन नेताओं को बुरे कामों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। चाहे उनके पापों के बारे में बाद में रिपोर्ट आएं, लेकिन भविष्य में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

जवाबदेही के बारे में दृढ़ रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, भाजपा की ढाल उन्हें दूसरे राज्यों में कानून के जाल से तो बचा सकती है, लेकिन पंजाब में नहीं। इन नेताओं को पंजाबियों को धमकाने से बाज आना चाहिए क्योंकि पंजाबी उन्हें उनकी असली स्थिति दिखा देंगे। उन्होंने आगे कहा, लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए इन नेताओं को पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा मारने के लिए सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके देश के संविधान का उल्लंघन कर रही है। यह विडंबना है कि उसी अशोक मित्तल को भाजपा ने जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की, जिसके ठिकानों पर कुछदिन पहले ईडी ने छापे मारे थे।

दल-बदल के हालात के बारे में उन्होंने कहा, यह भाजपा की बांह मरोड़ने वाली रणनीति है। राघव चड्ढा, जो कहा करता था कि भाजपा बिना डिटर्जेंट वाली वॉशिंग मशीन है, जहां राजनीतिक नेताओं के पाप धोए जाते हैं, अब उसी पार्टी से हाथ मिला रहा है। उन्होंने आगे कहा, राघव चड्ढा भगवा पार्टी में शामिल होकर बेतुकी बातें करने लगा है। उसे भाजपा में शामिल होने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा, मैं संकट की इस घड़ी में पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए विधायकों का धन्यवाद करता हूं। मैं इस शक्ति प्रदर्शन के लिए निजी तौर पर इन विधायकों का ऋणी

हूं। भाजपा की पंजाब के प्रति पहुंच पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, भाजपा को कभी भी पांच दरियाओं की इस धरती से जीतने का सपना नहीं देखना चाहिए। प्रदेश के लोग भाजपा के संदिग्ध चरित्र से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वे इसे सबक जरूर सिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा, भले ही भाजपा कुछ राज्यों में मिली जीत से उत्साहित है, जहां तक पंजाब का सवाल है, प्रदेश और उसके लोगों के प्रति उसके अन्याय और सौतेले व्यवहार की कहानी बहुत लंबी है। उन्होंने कहा, भाजपा पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी, झाकी, चंडीगढ़, भाखड़ा बांध और हर दूसरे वैध अधिकार से वंचित करना चाहती है।

वित्तीय चिंताओं के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, इन लोगों ने पंजाब के विकास को खतरे में डालने के लिए प्रदेश के वैध फंड रोक दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, हवाई किले बनाने के बजाय भाजपा नेतृत्व को यह भूल जाना चाहिए कि वह कभी पंजाब में सत्ता संभालेगा। पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ किए गए गुनाह माफ नहीं किए जा सकते। उन्होंने टिप्पणी की, भाजपा किस मुंह से पंजाब आएगी, जब उसके नेताओं ने कभी प्रदेश और उसके लोगों के मुद्दे नहीं उठाए ? पंजाब के बहादुर और समझदार लोग भाजपा के बुरे कामों को कभी नहीं भूलेंगे और उसे उचित सबक सिखाएंगे।

राजनीतिक वास्तविकता की पहचान कराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, भाजपा के पास इस समय प्रदेश में दो विधायक हैं, लेकिन जिस तरह से वह शेखी बघार रहे हैं, इससे उनकी सीटें शून्य हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, पंजाबी ऐसी तानाशाही चालों के आगे नहीं झुकते और हमेशा उन विभाजनकारी ताकतों को उचित सबक सिखाते हैं, जो पंजाब पर बलपूर्वक राज करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, जब से प्रदेश सरकार ने बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया है, भाजपा परेशान है क्योंकि वह पंजाब में अपने विभाजनकारी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाएगी।

सरकार का रुख दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब में बार-बार नकारने के बावजूद भाजपा ने डराने-धमकाने, लालच देने और दल-बदल के प्रयासों के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को कमजोर करने की कोशिशें करके प्रदेश के प्रति दुश्मनी वाला रवैया अपनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा, आप अपनी ताकत आम लोगों से प्राप्त करती है और एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है। ऐसी घिनौनी चालें लोकतंत्र में राजनीतिक जीत सुनिश्चित नहीं कर सकतीं। पंजाबी उन्हें उचित सबक सिखाएंगे।

दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर कहा, पंजाब के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी है। आज, सभी आप विधायकों के साथ हम पंजाब के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और राष्ट्रपति के सामने प्रदेश की मजबूत आवाज पेश करने के लिए निकले हैं। आपका जन सेवक होने के नाते हमारी सरकार पंजाब की खुशहाली सुनिश्चित करने और समाज के हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

नशा मुक्ति अभियान के तहत, पंजाब पुलिस ने 15 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़/लुधियाना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह की सोच के अनुरूप पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के तहत जालंधर और मोहाली के बाद अब लुधियाना राज्य का तीसरा ऐसा शहर बन गया है, जहां इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) स्थापित किया गया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) गौरव यादव ने अत्याधुनिक भावी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) के उद्घाटन के अवसर पर दी।

डीजीपी ने बताया कि आइसीसीसी परियोजना के तहत शहर की निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए 259 स्थानों पर 1,700 हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। शहर भर में 46 स्थानों पर स्थापित

यह आइटीएमएस 9 प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघनों का पता लगा सकता है, जिनमें लाल बत्ती पार करना, स्टॉप लाइन का उल्लंघन, बिना हेलमेट वाहन चलाना, पीछे बैठने वाले यात्री द्वारा हेलमेट न पहनना, तीन सवारी बैठाना, ओवरस्पीडिंग, जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन, गलत दिशा में वाहन चलाना और गलत पार्किंग शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव, जो ग्राउंड-जीरो दौरे के तहत लुधियाना में थे, ने अपग्रेड किए गए अत्याधुनिक आइसीसीसी को निवारक पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, नए उद्घाटित आइसीसीसी में एक ही छत के नीचे कई यूनिट्स को शामिल किया गया है, जिनमें ट्रैफिक, पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर), सेफ सिटी और वायरलेस यूनिट शामिल हैं। इससे पुलिस के कार्यों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा और पीसीआर रेस्पोंस समय 15 मिनट से घटाकर मात्र 7-8 मिनट कर दिया गया है।

डीजीपी, जिनके साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) लुधियाना स्वप्न शर्मा और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) लुधियाना रेंज सतिंदर सिंह भी मौजूद थे, ने फील्ड अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक भी की, जिसमें जन शिकायतों के त्वरित और नागरिक-केंद्रित समाधान पर जोर दिया गया।

आपसी समन्वय और एकजुटता को और मजबूत करने के लिए डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस लाइंस में आयोजित ह्यवड्डे खानेह्ल के दौरान पंजाब पुलिस के सभी रैंक के 550 से अधिक कर्मियों के साथ भोजन किया।

राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद बोले राघव चड्ढा, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है पंजाब सरकार

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर राज्य की मशीनरी के कथित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई। राघव चड्ढा ने बताया कि इस पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रपति से की गई है और उन्होंने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है।

राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी छोड़ कर अन्य दलों में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति तब और गंभीर हो गई जब उनके साथी सांसद संदीप

पाठक के खिलाफ दो ह्लदुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंतह्व एफआईआर दर्ज की गईं। उन्होंने बताया कि मीडिया के जरिए यह भी फैलाया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

राघव चड्ढा ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विजिलेंस, प्रदूषण बोर्ड और पंजाब पुलिस का इस्तेमाल बदले की भावना से करना एक खतरनाक खेल है। राघव चड्ढा ने कहा कि जब तक नेता ह्यआआपा में रहते हैं, उन्हें ईमानदार बताया जाता है, लेकिन पार्टी छोड़ते ही उन्हें भ्रष्ट करार दिया जाने लगता है।

गैंगस्टरों पर वार का 105वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 586 स्थानों पर छापेमारी; 249 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर शुरू की गई निर्णायक ह्यगैंगस्टरों ते वारह्ल मुहिम के 105वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के साथियों के पहचाने और मैप किए गए 586 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरों ते वार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसे 20 जनवरी 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू किया गया था। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं। 105वें दिन, पुलिस टीमों ने एक हथियार सहित 249 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे इस अभियान की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 26,729 हो गई है। इसके अलावा 77 व्यक्तियों के विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 33 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान चार भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं भी साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के विरुद्ध अपनी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध को 430वें दिन भी जारी रखते हुए आज 126 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 614 ग्राम हेरोइन, 733 नशीली गोलियां/कैप्सूल तथा 1350 रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही केवल 430 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 62,639 हो गई है।

पुलिस टीमों ने 77 व्यक्तियों के विरुद्ध की एहतियाती कार्रवाई, 33 को पूछताछ के बाद रिहा किया गया

डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने गांव साधोवाल में 43.22 लाख रुपये की लागत से बने मुख्यमंत्री खेल मैदान को किया लोक अर्पित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़ / गढ़शंकर
(होशियारपुर)

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा राज्य में खेलों को प्रोत्साहित करने और युवाओं को सही दिशा की ओर प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गांव साधोवाल में 43.22 लाख रुपये की लागत से तैयार किए गए आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री खेल मैदान का आज पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री जय कृष्ण सिंह रौड़ी द्वारा रिबन काटकर लोक अर्पित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब की प्रगति में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें खेलों की ओर प्रेरित करना समय की

मांग है। उन्होंने कहा कि खेल मैदान केवल खेलने की जगह नहीं होते, बल्कि ये अनुशासन, स्वस्थ जीवन और टीम वर्क की भावना को भी मजबूत करते हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार गांवों और शहरों में खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इन खेल मैदानों के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को उच्च स्तर की सुविधाएं मिलेंगी, जिससे वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना तथा अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सकेंगे।

डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नशों के खात्मे के लिए ऐसे खेल मैदान युवाओं को सही दिशा की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लें और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखें।

इस अवसर पर गांव साधोवाल की पंचायत, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, खेल प्रेमियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। गांव वासियों ने डिप्टी स्पीकर रौड़ी का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह खेल मैदान गांव के लिए एक बड़ी सौगात है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

अंत में डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल मैदान की देखभाल और सुव्यवस्थित प्रबंधन को सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि युवा इसका पूरा लाभ ले सकें।

बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने तूफान से हुए नुकसान के बाद बहाली प्रयासों की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की; पीएसपीसीएल के शानदार प्रयासों की सराहना की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब में 3 मई की सुबह आए भीषण तूफान के बाद बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नुकसान का आकलन करने, बहाली प्रयासों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में पीएसपीसीएल के चेयरमैन, निदेशक, मुख्य अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। स्थिति की व्यापक समीक्षा से पता चला कि तूफान से मोहाली, पटियाला, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर और गुरदासपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि 66 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क बड़े स्तर पर सुरक्षित रहा, लेकिन वितरण ढांचे को काफी नुकसान हुआ। लगभग 1300 (11 केवी) फीडर खराब हो गए, करीब 1500 बिजली के खंभे टूट गए, 300 से अधिक ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए और 70 किलोमीटर से अधिक एचटी/एलटी लाइनें क्षतिग्रस्त हुईं। इसके अलावा 220 केवी का एक ट्रांसमिशन टावर भी क्षतिग्रस्त हुआ। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बिजली कटौती तीन गुना अधिक रही, जिससे लगभग 8 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ।

बिजली मंत्री ने पीएसपीसीएल की टीमों के तत्पर और समन्वित प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दिन-रात काम किया। उल्लेखनीय है कि पूरे पंजाब में

83,000 से अधिक शिकायतों का निपटारा किया गया, जिनमें से लगभग 70% शिकायतें केवल दो घंटे के भीतर ही हल कर दी गईं, जबकि शेष मामलों में बड़े बुनियादी ढांचे की क्षति शामिल थी, जिनके लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।

पीएसपीसीएल की निरंतर निगरानी, रियल-टाइम समन्वय और व्यापक फीडर गश्त के कारण 24 घंटे के भीतर सभी प्रभावित क्षेत्रों में मुख्य नेटवर्क या वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से बिजली आपूर्ति सफलतापूर्वक बहाल कर दी गई। सिस्टम को और स्थिर बनाने के लिए क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली को प्राथमिकता दी जा रही है।

बैठक के दौरान संजीव अरोड़ा ने पीएसपीसीएल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए: भविष्य में ऐसी अप्रत्याशित मौसम संबंधी घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपदा तैयारी प्रणाली को मजबूत किया जाए। बाधाओं को न्यूनतम करने के लिए निवारक रखरखाव और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाए। तेज प्रतिक्रिया प्रणाली और क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय सुनिश्चित किया जाए। शीघ्र समाधान के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया जाए।

मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि आपातकालीन स्थितियों में बहाली में देरी के प्रति शून्य सहनशीलता होनी चाहिए और अधिकारियों को आने वाले महीनों में ऐसी किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजाब सरकार की राज्य के लोगों को विश्वसनीय, निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। उन्होंने इतने कम समय में सामान्य स्थिति बहाल करने में पीएसपीसीएल के फील्ड स्टाफ, इंजीनियरों और अधिकारियों के समर्पण और अथक प्रयासों की सराहना की।

उपभोक्ताओं को हुई असुविधा को स्वीकार करते हुए मंत्री ने पंजाब के लोगों का उनके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि पूरे राज्य में अधिक मजबूत और व्यवस्थित बिजली बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

संक्षिप्त-समाचार

फाजिल्का में भारत-पाक सीमा पर खेती करने गया किसान करंट से झुलसा

चंडीगढ़। भारत-पाकिस्तान सीमा पर फाजिल्का सेक्टर में खेती करने गया एक किसान हादसे का शिकार हो गया। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से किसान बुरी तरह से झुलस गया। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया है। फाजिल्का के सीमावर्ती गांव मुहार खीवा मनसा निवासी घायल किसान के बेटे बिट्टू सिंह ने बताया कि उनके परिवार की करीब 9 एकड़ जमीन अंतरराष्ट्रीय तारबंदी के उस पार स्थित है, जहां वे रोजाना खेती करने जाते हैं। घटना के दिन भी उनके पिता खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान मोटर चलाने के लिए वह ट्रांसफार्मर पर तार लगाने चढ़े, तभी अचानक हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए और बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और बीएसएफ जवानों ने तुरंत मदद करते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया।

सजा पूरी होने पर चार पाकिस्तानी कैदी रिहा

चंडीगढ़। भारत सरकार ने सजा पूरी कर चुके चार पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। सभी कैदियों को मंगलवार को अटारी-बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद इन्हें पाकिस्तानी रेंजरों के हवाले कर दिया।रिहा किए गए कैदियों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद रजा, मोहम्मद हमजा और हुसैन शामिल हैं। इनमें से एक कैदी ने लगभग 10 साल की सजा काटी, जबकि अन्य ने 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल में समय बिताया। पुलिस सुरक्षा के बीच इन्हें अटारी बॉर्डर तक लाया गया, जहां जरूरी दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने और जांच के बाद पाकिस्तान भेज दिया।मोहम्मद हमजा ने बताया कि वह नशे की हालत में गलती से सीमा पार कर गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने करीब एक साल से अधिक समय भारत की जेल में बिताया। उसने यह भी बताया कि उसके परिवार को उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसी प्रकार अन्य कैदी भी सीमा पार आ गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह रिहाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।

चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट में पावर बैंक फटा, पांच यात्री चोटिल

चंडीगढ़। हैदराबाद से चंडीगढ़ आई इंडिगो की फ्लाइट में मंगलवार को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पावर बैंक फट गया। यह घटना उस समय हुई, जब फ्लाइट एयरपोर्ट पर खड़ी थी। इस घटना में पांच यात्री चोटिल हो गए। इस स्थिति को देखते हुए फ्लाइट स्टाफ ने इमरजेंसी डोर खोले और यात्रियों को बाहर निकाला। पूरे जहाज को खाली करके जांच की गई। दोपहर बाद हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री का पावर बैंक फट गया। इंडिगो स्टाफ ने तुरंत इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी और आपात स्वीकृति के साथ विमान खाली कराया गया। ग्राउंड टीमें भी मौके पर पहुंचीं और यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाया गया। बताया गया कि इंडिगो की फ्लाइट 6ई -108 करीब 3:29 बजे चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरी। विमान में 198 यात्री, दो बच्चे और छह क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग के बाद जब विमान वे नंबर-1 की ओर बढ़ रहा था, तभी सीट 39 सी पर बैठे यात्री ने क्रू को अपने पावर बैंक में आग लगने की जानकारी दी। आशंका जताई गई कि पावर बैंक फट गया था। कैबिन क्रू ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन विमान के अंदर धुआं फैल गया। एहतियात के तौर पर इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किए गए। बताया गया कि करीब 3:35 बजे क्रू मेंबर ने इमरजेंसी एग्जिट खोला और यात्रियों को स्लाइड्स के जरिए बाहर निकाला गया। इस बीच एयरफोर्स की फायर टेंडर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी। हवाई अड्डा प्रबंधकों के अनुसार कुछ यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति सामान्य होने पर घर भेज दिया गया है। एयरपोर्ट सीईओ अजय वर्मा ने कहा कि संबंधित एयरलाइन से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।

प्रुडंट कॉरपोरेट एडवायजरी सर्व्हिसेस लिमिटेड ने बिजनेस मैनेजमेंट टूल शुरू किया

चंडीगढ़। प्रुडंट कॉरपोरेट एडवायजरी सर्व्हिसेस लिमिटेड ने अपने एआई-सक्षम बिजनेस मैनेजमेंट टूल के शुभारम्भ की घोषणा की। इस टूल से पार्टनर्स और स्मार्ट तरीके से आयोजन कर सकेंगे, ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकेंगे और मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकेंगे और प्रीसशन के साथ अपने बिजनेस की प्रगति कर सकेंगे। जिस तरह से हमारे म्युच्युअल फंड वितरक ग्राहकों को जान सकते है, उतना अच्छा तो कोई सॉफ्टवेअर कभी जान नही सकता है यह भावनात्मक निदेर्शाक है और वह हमेशा पार्टनर के साथ रहेगा। एज+ बौद्धिक निदेर्शाक एक ऐसी मदद करने वाली प्रणाली है जो हर पार्टनर का कार्य तेजी और तीव्रता से आगे बढाएगी और आने वाले समय के लिए उसे तैयार करेगी। पार्टनर को सबसे करीब होने वाले दो परिणामों को ध्यान में रखते हुए एज+ को बनाया गया हैः बिजनेस की प्रगति और समय की बचत। अब सिर्फ मिनटों में वितरक अपने ग्राहकों को उद्देश्य आधारित सोल्युशन्स दे सकेंगे। ग्राहक की जोखीम प्रोफाईल और निवेश की रूपरेखा की जानकारी देने के बाद एआई तुरन्त इक्विटी, डेब्ट और हायब्रिड इन्स्ट्रुमेंटस को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ संसाधन अलोकेशन तैयार करेगा और साथ ही योजना के लिए विशेष सुझाव देगा। पार्टनर्स रेडीमेड उपलब्ध इमेल सन्देश भेज सकेंगे और उसी एआई पॉवर्ड स्क्रीन के द्वारा ट्रान्जैक्शन्स भी कर सकेंगे। अब अपने वर्तमान स्थान पर बैठे बैठे वितरक हर विस्तार के अवसर को जाँच सकते हैं और उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। उम्र- आधारित और एयुएम- आधारित सेगमेंटस के होने से वितरकों को ग्राहकों के लिए उचित उत्पादों के लिए पिच करने में मदद मिलेगी।

फिनवेसिया ने एआई लॉन्च किया

चंडीगढ़। वैश्विक मल्टी-डिसिप्लिनरी संगठन फिनवेसिया ने एआई के लॉन्च की घोषणा की, जो भारत का पहला वॉयस-टू-वॉयस एआई फाइनेंस बडी है। यह जंप्प प्लेटफॉर्म में यस बैंक के साथ साझेदारी में इंटीग्रेट किया गया है, जो ऐप-आधारित मनी मैनेजमेंट से बातचीत-आधारित वित्तीय मार्गदर्शन की ओर बदलाव को दशार्ता है।अकको रोजमर्रा के वित्तीय प्रबंधन को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह उपयोगकताओं को अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सीधे बोलने और रियल-टाइम, बातचीत-आधारित मार्गदर्शन प्राप्त करने की सुविधा देता है। यह खर्च ट्रैक करने, बजट मैनेज करने और बचत की योजना बनाने में मदद करता है-बिना जटिल डैशबोर्ड या मैनुअल ट्रैकिंग के। पारंपरिक वित्तीय टूल्स अक्सर सिस्टम-आधारित इंटरैक्शन पर निर्भर होते हैं, जो कई बार जटिल और सीमित लगते हैं।अकएक अलग दृष्टिकोण अपनाता है, जो इस समझ पर आधारित है कि लोग अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में प्राकृतिक और मानवीय बातचीत में अधिक सहज महसूस करते हैं। यह एक वॉयस-फर्स्ट अनुभव प्रदान करता है, जो पारंपरिक चैटबॉट्स से आगे जाकर उपयोगकर्ता के व्यवहार के अनुसार खुद को ढालता है और रियल-टाइम निर्णय लेने में मदद करता है। जंप्प के सीईओ सरवजीत सिंह विर्क ने कहा कि पैसे का प्रबंधन अब बेहद व्यक्तिगत हो गया है। इसे आपके डेटा से शुरू होकर आपके वित्तीय व्यवहार के अनुसार विकसित होना चाहिए।अकके माध्यम से हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो रोजमर्रा की बातचीत को उपयोगी वित्तीय इनसाइट्स में बदल देता है और उपयोगकताओं को अपने वेल्थ क्रिएशन लक्ष्यों की स्पष्ट दिशा दिखाता है।

बीआरएफईडीएफ ने शिपिंग लाइन प्रथाओं में मुद्दों को उजागर किया

चंडीगढ़। पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग (डीजी शिपिंग), भारत सरकार ने निर्यातकों और उद्योग हितधारकों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की। इस बैठक में मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण समुद्री सेवाओं में आई रुकावटों से उत्पन्न संकट पर चर्चा की गई। इस बैठक में औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि निर्यातकों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वे अलग-अलग घटनाएं नहीं बल्कि व्यवस्थागत और व्यापक हैं। ये चुनौतियां विभिन्न क्षेत्रों, बंदरगाहों और शिपमेंट श्रेणियों को एक साथ प्रभावित कर रही हैं, जिनके समाधान के लिए नीति-स्तरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, एफएमसीजी और हस्तशिल्प सहित विभिन्न उद्योगों के निर्यातकों ने बताया कि वैश्विक शिपिंग लाइनों की एकतरफा कार्रवाइयों के कारण उन्हें गंभीर परिचालन और वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। सेवाओं के निलंबन, मार्ग परिवर्तन और कार्गो डायवर्जन के कारण कंटेनर विभिन्न बंदरगाहों, आईसीडी और ट्रांसशिपमेंट हब्स में फंसे हुए हैं। कार्गो आवाजाही बाधित होने के बावजूद निर्यातकों को डिटेंशन, डेमुरेज और अनेक अतिरिक्त शुल्क लगातार चुकाने पड़ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका मित्तल, चेयरपर्सन, बासमती राइस फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम (बीआरएफईडीएफ) ने कहा, हम डीजी शिपिंग द्वारा निर्यातकों की शिकायतों को औपचारिक रूप से दर्ज करने और समस्या की गंभीरता को स्वीकार करने के इस सक्रिय कदम की सराहना करते हैं।

नेपाल सरकार के ट्रेड यूनियन खत्म करने के फैसले के खिलाफ कर्मचारी संगठन अदालत जाने की तैयारी में

छह कर्मचारी संगठनों ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे अस्वीकार करने की घोषणा की

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

नेपाल सरकार द्वारा सिविल सेवा कर्मचारी ट्रेड यूनियन को समाप्त करने के निर्णय पर छह कर्मचारी संगठनों ने कड़ा एतराज जताते हुए इसे अस्वीकार करने की घोषणा की है। उन्होंने इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है।

मंगलवार को जारी प्रेस बयान में नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियन, नेपाल राष्ट्रीय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मंच और स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठन के केंद्रीय अध्यक्षों ने सरकार के इस कदम को मनमाना बताते हुए खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के संविधान की धारा 17 और धारा 34, प्रचलित ट्रेड यूनियन तथा श्रम कानून, 1948 की मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की धारा 20, तथा श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय महासंधि संख्या 7, 9, 144, 151 और 154 के अनुसार श्रमिकों और राष्ट्र सेवकों को संगठित होने का अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों की रक्षा करते हुए सभी कर्मचारियों के पेशागत विकास को सुनिश्चित करने के लिए संघीय सिविल सेवा कानून को तुरंत लागू करने की भी उन्होंने मांग की है। वर्तमान सरकार द्वारा छीने गए ट्रेड यूनियन अधिकारों की पुनर्स्थापना की मांग करते हुए कर्मचारी संगठनों ने आवश्यक होने पर कानूनी लड़ाई लड़ने की चेतावनी दी है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की सरकार द्वारा हाल ही में कानूनों में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिसे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने अनुमोदित किया। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद दशकों से चला आ रहा कर्मचारी ट्रेड यूनियन समाप्त हो गया।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
मिति २०८३/०१/२१
नेपाल सरकारले मिति २०८३।०१।२० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ मार्फत निजामती सेवा ऐन,२०४९ लाई संशोधन गरेको विषयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको यस स्वेच्छाचारि कदमप्रति खेद प्रकट गर्दछौं। [illegible]

छात्र संगठन और ट्रेड यूनियन खत्म करने को लेकर नेपाल के पीएम ने दी सफाई

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र और कर्मचारी संगठनों को खत्म करने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए इसपर सफाई दी है। उनका तर्क है कि शैक्षणिक संस्थानों और कर्मचारी तंत्र में वर्षों से जड़ जमा चुकी दलगतकरण (पार्टीकरण) को समाप्त कर व्यवस्था सुधार के लिए सरकार ने इन संगठनों को खत्म करने का निर्णय लिया है। मंगलवार सुबह सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि छात्र और कर्मचारी संगठन पेशागत हित से अधिक राजनीतिक दलों के ह्वास्लीपर सेलह्व बन गए थे, इसलिए यह नया निर्णय दोनों- कर्मचारियों और छात्रों के हित में लिया गया है। उन्होंने लिखा, योग्यता से अधिक पहुँच और क्षमता से अधिक झोला और झंडे का महत्व बढ़ने से पूरी व्यवस्था पर जनता का विश्वास कमजोर हुआ है। इसलिए स्पष्ट निर्णय आवश्यक था–शैक्षणिक संस्थानों में दल का झंडा और कर्मचारी तंत्र में दल का झोला निषेध। उनका कहना है कि यह नई व्यवस्था किसी के अधिकारों को नहीं छीनती बल्कि पेशागत स्वतंत्रता को और मजबूत बनाएगी। अब नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति का आधार राजनीतिक निकटता नहीं बल्कि नियम, योग्यता और दक्षता होगी- यह भी उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, यह कदम किसी विशेष पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है बल्कि देश को दलगत कब्जे से निकाल कर संस्थागत मार्ग पर लाने का प्रयास है। बदलाव भाषण से नहीं, निर्णय से आता है। हम जो भी करते हैं, आम जनता के हित में करते हैं।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच करेगी ईडी

एजेंसी (हि.स.)
अंबिकापुर/रायपुर

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुरू कर दी है। इस घोटाले का खुलासा पिछले साल मई 2025 में ऑडिट के दौरान हुआ था, जिसके बाद 31 मई 2025 को बैंक मैनेजर सहित 4 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त किया गया था। शनिवार को ही बैंक के सीईओ ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की कि घोटाले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की टीम को सौंप दिए गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की आधिकारिक जांच शुरू हो चुकी है। सहकारी बैंक के सीईओ ने इसकी पुष्टि की है।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कलेक्टर विलास भोस्कर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जून 2025 के दौरान राज्य शासन के माध्यम से ईडी और सीबीआई से जांच कराने हेतु प्रमुख सचिव को पत्र लिखा था। कलेक्टर की रिपोर्ट और सिफारिश के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने औपचारिक रूप से प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए पत्र भेजा। राज्य शासन के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के लिए अपनी मंजूरी दी और अब रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने इसकी पूरी फाइलें मंगा ली हैं। सरगुजा सहकारी बैंक घोटाले में 4 मई 2026 को आई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने अब इस मामले की कमान पूरी तरह संभाल ली है। एजेंसी अब मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि गबन किए गए 28 करोड़ को कहां निवेश किया गया और किन संपत्तियों में बदला गया। मुख्य घोटाले के बीच ही सरगुजा के केरजू सहकारी समिति में एक और नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहाँ 127 किसानों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर 1.93 करोड़ का लोन निकाला गया है। बैंक में घोटाला करीब एक साल पहले सामने आया था, जब तत्कालीन सरगुजा कलेक्टर, विलास भोस्कर ने बैंक की शंकरगढ़ और कुसमी ब्रांचों के खातों की जांच करवाई थी। जांच में करीब 28 करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, शंकरगढ़ शाखा के बैंक मैनेजर अशोक कुमार सोनी ने बैंक में फर्जी खाते खोलकर बड़ी मात्रा में पैसे की हेराफेरी की।

इन फर्जी खातों से नकद राशि की निकासी के अलावा कई ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए गए। इस घोटाले में किसानों के केसीसी फंड, मनरेगा खातों और ग्राम पंचायतों की राशि का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, पुलिस ने पहले ही बैंक मैनेजर अशोक सोनी सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 4 बैंक अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 3 कर्मचारी घोटाला उजागर होने से पहले रिटायर हो चुके थे। सहकारी बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने बताया कि ईडी की टीम अभी तक सरगुजा नहीं आई है, लेकिन उन्होंने जांच से संबंधित सभी रिपोर्ट शनिवार को भेज दी हैं।

यूएई के फुजैराह तेल संयंत्र पर हमला ड्रोन और मिसाइल से भड़की आग

एजेंसी (हि.स.)
अबू धाबी/फुजैराह

संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोलियम साइट पर हमले के बाद भीषण आग लगने की खबर है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले के बाद सामने आई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।

फुजैराह मीडिया कार्यालय के अनुसार, हमले के तुरंत बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री एरिया में आग तेजी से फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवाओं की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और बुझाने का काम शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक, इस हमले में तीन भारतीय घायल हुए हैं। इससे पहले, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि देश की ओर कुछ मिसाइलें दागी गई थीं। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से कई मिसाइलों को वायु रक्षा प्रणाली ने रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। हालांकि, कुछ हमलों के कारण सीमित स्तर पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कि फुजैराह, जो यूएई का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा और तेल निर्यात केंद्र है, पर हमला क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है। हाल के दिनों में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और टकराव की घटनाओं ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के इलाकों में पहले से ही तनाव बना हुआ है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और बाजारों पर असर डाल सकती हैं।

बंगाल की प्रचण्ड जीत के बाद दिल्ली के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचे और पूजा-अर्चना की। उन्होंने मां काली का आशीर्वाद लिया और इस जीत को जनता के विश्वास और बदलाव का प्रतीक बताया। उनके साथ बांसुरी स्वराज और वीरेंद्र सचदेवा सहित कई नेता मौजूद रहे। मिनी बंगाल के नाम से जाने जाने वाले चितरंजन पार्क के लोगों ने नितिन नवीन का अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने शंख की ध्वनि के बीच पूरे विधि विधान के साथ काली मां की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। काली बाड़ी में पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि वे पश्चिम बंगाल और उन सभी राज्यों के लोगों को बधाई देते हैं, जहां चुनाव हुए। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाया जा सकता है। नितिन नवीन ने सभी राज्यों में शांति और समृद्धि बनी रहने की कामना की।

नेपाल ने एशियाई विकास बैंक से नए नेतृत्व की भावना के अनुसार सहयोग की अपील की

एजेंसी (हि.स.)
काठमांडू

फोटोः हि.स.

एशियाई विकास बैंक की 59वीं वार्षिक बैठक में नेपाल की तरफ से कहा गया है कि देश का नया राजनीतिक नेतृत्व एडीबी और अन्य विकास साझेदारों के साथ सहयोग को और गहरा करना चाहता है।

उज्बेकिस्तान के समरकंद में जारी इस बैठक के दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक को नेपाल की ओर से अस्थायी वैकल्पिक गवर्नर के रूप में संबोधित करते हुए अर्थ मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध महाशाखा प्रमुख डा. धनीराम शर्मा ने यह बात कही। एडीबी के बोर्ड में सामान्यतः अर्थमंत्री गवर्नर होते हैं, लेकिन बजट निर्माण में व्यस्त रहने के कारण डा. स्वर्णिम वाग्ले इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसलिए अस्थायी वैकल्पिक गवर्नर के रूप में डा. शर्मा ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नेपाल में वर्तमान में एक स्थिर और सुधारोन्मुख सरकार है, जिसे आर्थिक रूपांतरण को तेज करने, गुणवत्तापूर्ण निवेश आकर्षित करने और समावेशी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने का स्पष्ट जनादेश प्राप्त है। उन्होंने यह भी बताया कि इस जनादेश को पूरा करने के लिए नेपाल सरकार एडीबी जैसे अपने सबसे बड़े बहुपक्षीय विकास साझेदार के साथ सहयोग को विशेष महत्व दे रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल उच्च प्रभाव वाले निवेश को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा, हम जलविद्युत, बुनियादी ढांचा, डिजिटल कनेक्टिविटी, कृषि और पर्यटन में निवेश विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए हम एडीबी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वह ब्लेंडेड फाइनेंस और गैर-सरकारी (नॉन-सॉवरेन) वित्त जैसे नए वित्तीय उपकरणों का विस्तार करे, जिससे निजी पूंजी को बड़े पैमाने पर परिचालित किया जा सके।

ऊर्जा रणनीति तैयार करने के दौरान नेपाल को एक प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा साझेदार के रूप में प्राथमिकता देने का भी उन्होंने आग्रह किया।

संक्षिप्त-समाचार

मुंबई-दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसा, सूरत के एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत

पंचमहल। पंचमहल जिले में मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर पर गोधरा के पास हादसे में कार सवार सूरत के एक ही परिवार के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार की एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में माता, पिता और पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, उनकी पुत्री को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही वेजलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अज्ञात वाहन चालक की तलाश भी तेज कर दी गई है।

सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च हुआ रिकोड स्टूडियोज का आईपीओ

नई दिल्ली। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के लिए काम करने वाली कंपनी रिकोड स्टूडियोज का 44.59 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में सात मई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद आठ मई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 11 मई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 12 मई को बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 150 रुपये से लेकर 158 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 800 शेयर का है। रिकोड स्टूडियोज के इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स को दो लॉट यानी 1,600 शेयरों के लिए बोली लगाना होगा, जिसके लिए उन्हें 2,52,800 रुपये का निवेश करना होगा। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 28,22,400 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 23,58,400 नए शेयर और 3,19,200 शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा 1,44,800 नए शेयर मार्केट मेकर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए 47.36 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर्स के लिए 33.22 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए 14.29 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इसके अलावा मार्केट मेकर के लिए 5.13 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इस इश्यू के लिए सेरेन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि मुद्रा आरटीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। वहीं, असनानी स्टॉक ब्रोकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मार्केट मेकर है।

स्टॉक मार्केट में अंबा ऑटो की कमजोर शुरूआत, घाटे में कंपनी के आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम करने वाली कंपनी अंबा ऑटो सेल्स एंड सर्विसेज लिमिटेडट के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में कमजोरी के साथ एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को करारा झटका दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 135 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 0.37 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 134.50 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद बिकवाली का दबाव बन जाने कारण ये शेयर थोड़ी देर में ही गिर कर 127.80 रुपये के लोअर सर्किट लेवल तक गिर गया। हालांकि बाद में खरीदारों ने लिवाली का जोर बनाया, जिससे लोअर सर्किट ब्रेक हो गया। सुबह 11 बजे तक का कारोबार होने के बाद कंपनी के शेयर 132.35 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इस तरह अभी तक के कारोबार के बाद कंपनी के आईपीओ निवेशक 1.96 प्रतिशत के नुकसान में थे। अंबा ऑटो का 65.12 करोड़ रुपये का आईपीओ 27 से 29 अप्रैल के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से एवरेज रिस्पॉन्स मिला था, जिसके कारण ये ओवरऑल 1.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 1.75 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 1.47 गुना सब्सक्रिप्शन आया था। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व पोर्शन सिर्फ 0.70 गुना सब्सक्राइब हो सका था। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले 48.24 लाख नए शेयर जारी किए गए हैं। आईपीओ के जरिये जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपना नया शोरूम बनाने, मौजूदा शोरूम का रिनोवेशन करने, वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों में करेगी।

सर्राफा बाजार में सोने की घटी चमक, चांदी में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में मंगलवार के शुरुआती कारोबार के दौरान सोने के भाव में कमजोरी का रुख नजर आ रहा है। भाव में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,49,610 रुपये से लेकर 1,51,260 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना आज 1,37,140 रुपये से लेकर 1,38,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। वहीं, चांदी की कीमत में मंगलवार कोई बदलाव नहीं होने के कारण दिल्ली सर्राफा बाजार में ये चमकीली धातु आज भी शुरुआती कारोबार के दौरान 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर ही बिक रही है। दिल्ली में मंगलवार 24 कैरेट सोना 1,49,760 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,290 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,49,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,190 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना मंगलवार 1,51,260 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,38,790 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,49,610 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,37,140 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का कल होगा विस्तार, गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह

एजेंसी (हि.स.)
पटना

फोटोः हि.स.

बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बहुप्रतीक्षित विस्तार को लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष संजय सरावगी ने मंगलवार को जानकारी दी कि 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा, जिसमें कई बड़े राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक, समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति तय मानी जा रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के शीर्ष नेतृत्व द्वारा नए मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर गांधी मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। वहां एक भव्य मंच का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए बैठने की व्यापक व्यवस्था की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर विस्तृत योजना बनाई जा रही है, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। उल्लेखनीय है कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दो उपमुख्यमंत्रियों के साथ शपथ ली थी। तभी से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही थीं, जो अब 7 मई को खत्म होने जा रही हैं।

मलयालम अभिनेता संतोष नायर का निधन

मुंबई। मलयालम सिनेमा के जाने-माने अभिनेता संतोष नायर का 65 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार, केरल के पथानामथिट्टा जिले में उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें वह, उनकी पत्नी और ट्रक चालक घायल हो गए। सभी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान अचानक आए हार्ट अटैक के कारण अभिनेता ने दम तोड़ दिया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों में शोक की लहर है। संतोष नायर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1982 में फिल्म 'इथु नजालुदे कथा' से की थी। इसके बाद उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम करते हुए अपने अभिनय का लोहा मनवाया। उन्होंने मुख्य किरदारों के साथ-साथ खलनायक और हास्य भूमिकाओं में भी अपनी अलग पहचान बनाई, जिससे वह मलयालम सिनेमा के बहुमुखी कलाकारों में गिने जाते थे। उनकी आखिरी फिल्म 'मोहिन्याट्टम' इन दिनों सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है और यह 8 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में साईजू कुरुप और सूरज वेंजरमूडु भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। संतोष नायर के निधन से फिल्म जगत ने एक अनुभवी और प्रतिभाशाली कलाकार को खो दिया है।

बिहार में 24 घंटे में आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली से 24 लोगों की मौत

एजेंसी (हि.स.)
पटना

राज्य के अलग-अलग हिस्सों में सोमवार शाम से देर रात तक तेज आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 07 बच्चों समेत कुल 24 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। राज्य सरकार ने मृतक आश्रित परिवारों को तुरंत 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा गयाजी में 6 लोगों जान गई है। वहीं, पूर्वी-पश्चिमी चंपारण में भी 6 लोगों की मौत हुई है। बीते सोमवार को देर शाम अचानक मौसम ने भयावह रूप ले लिया। आसमान काले बादलों से घिर गया। तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। राज्यभर में बिजली गिरने और पेड़ गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आकाशीय बिजली व आंधी-तूफान से हुई मौत पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतक आश्रित परिवारों को तुरंत 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे बेहद संवेदनशील बताए हैं। मंगलवार को 18 जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और अरवल में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पटना समेत 10 जिलों में रेड अलर्ट लागू है। इससे पहले, पटना में 39 मिलीमीटर और गया में सबसे अधिक 47 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला बागमाने प्राइम ऑफिस का आईपीओ, 7 मई तक लगा सकते हैं बोली

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

प्राइम ऑफिस स्पेस मार्केटिंग के काम में लगी कंपनी बागमाने प्राइम ऑफिस आरईआईटी का 3,405 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 7 मई तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 12 मई को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 13 मई को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 15 मई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं।

इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 95 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। इस आईपीओ के तहत कुल 34.05 करोड़ शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 23.90 करोड़ नए शेयर और 10.15 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए अधिकतम 75 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसी तरह नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। बागमाने प्राइम ऑफिस आरईआईटी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी को 809.36 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था, जो अगले वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 897.10 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

असम चुनाव सीएम की भविष्यवाणी हुई सच, एनडीए की ऐतिहासिक जीत

मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने भाजपा के चुनावी भविष्यवाणी का पुराना नोट किया शेयर

एजेंसी (हि.स.)
गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रदर्शन की सटीक भविष्यवाणी की थी। नतीजे घोषित होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पुराना नोट शेयर किया है।

डॉ. सरमा ने लिखा है कि 9 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने के बाद, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, मैंने कागज पर अपना खुद का अनुमान लिखा था। समय बीता, नतीजे आए और कल असम की जनता के अभूतपूर्व आशीर्वाद ने एक नया इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नतीजे उनकी उम्मीदों से थोड़े ज्यादा रहे। सौ से ज्यादा सीटों के साथ उम्मीद से एक ज्यादा हमारा अनुमान सही साबित हुआ है। यह जनादेश सिर्फ.एक संख्या नहीं है; यह असम की जनता के अटूट विश्वास और स्नेह को दर्शाता है। इस विश्वास और प्यार के लिए मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूँगा।

अंतिम नतीजों के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में निर्णायक जीत हासिल की और 102 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया।

अकेले भाजपा ने 82 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी, असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 10-10 सीटें जीतीं, जिससे गठबंधन आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर गया।

यह नतीजा असम में भाजपा का लगातार तीसरा कार्यकाल है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में उसके वर्चस्व को और मजबूत करता है। जनादेश का यह पैमाना, अलग-अलग क्षेत्रों में सत्ताधारी गठबंधन के शासन और संगठनात्मक ताकत के प्रति मतदाताओं के लगातार समर्थन को दर्शाता है।

हंसराज पब्लिक स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

- शिविर का उद्देश्य स्कूली बच्चों को विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना: अजय घनघस

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के तत्वावधान में हंसराज पब्लिक स्कूल में आज एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव श्री अजय कुमार घनघस ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य स्कूली बच्चों को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। उन्होंने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य छात्रों के बीच विधिक जागरूकता फैलाना और जमीनी स्तर पर न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक चरण में ही विधिक जागरूकता बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए सशक्त बनाती है और उन्हें दैनिक जीवन में कानून के महत्व को समझने में मदद करती है।

इस दौरान, डीएलएसए की पैनल अधिवक्ता सुश्री कोम्पल और सुश्री मेघा ने एनएएलएसए की बाल-अनुकूल विधिक सेवा योजना पर विस्तृत व्याख्यान दिए। उन्होंने इस योजना के प्रावधानों और लाभों को सरल और रोचक तरीके से समझाया, जिससे छात्रों को यह समझने में आसानी हुई कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किस प्रकार की विधिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। उन्होंने छात्रों को एनएएलएसए और एचएएलएसए द्वारा लागू की गई विभिन्न विधिक सहायता योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी, जो विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए हैं।

छात्रों को मुफ्त विधिक सहायता सेवाओं की उपलब्धता और सहायता प्रदान करने में विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका के बारे में सूचित किया गया। डीएलएसए और एनएएलएसए के महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर भी साझा किए गए, और छात्रों को किसी भी विधिक समस्या या आपात स्थिति में सहायता लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

श्री घनघस ने उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले का उचित समाधान किया जाएगा। उन्होंने रोगियों के लिए बेहतर रहन-सहन की स्थिति सुनिश्चित करने हेतु केंद्र में साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी किए। दिन भर की गतिविधियों ने कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित संस्थानों की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के प्रति डीएलएसए पंचकूला की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

नगर निगम चुनाव-2026: पंचकूला में तैयारियां पूरी: सतपाल शर्मा

सिटी दर्पण संवाददात
पंचकूला

- वार्ड-वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारी तैनात
- घर-घर वोटर स्लिप वितरण अभियान तेज
- मेयर के लिए 6, पार्षद पद के लिए 87 उम्मीदवार मैदान में

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के निदेर्शानुसार नगर निगम चुनाव-2026 के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए वार्ड-वार ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित करने का कार्य तेजी से जारी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया की मेयर पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि नगर निगम के 20 वार्डों में पार्षद पद के लिए 87 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी वार्डों में कुल 204 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ईवीएम मशीनों की प्रथम रैंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

श्री शर्मा ने नागरिकों से अपील की कि वे मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो वोटिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी–एक मेयर पद के लिए और दूसरी पार्षद के लिए–ताकि मतदाता अलग-अलग वोट डाल सकें। मेयर और वार्ड सदस्यों के लिए मतदान 10 मई को आयोजित होगा।

उन्होंने बताया कि मेयर पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तथा पार्षद पद के लिए 7.50 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही नगर निगम चुनावों के लिए डीईटीसी पंचकूला को व्यय प्रेक्षक (एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर) नियुक्त किया गया है। उम्मीदवारों को मतगणना के एक महीने के भीतर अपने चुनावी खर्च का विस्तृत ब्यौरा जिला चुनाव कार्यालय में जमा कराना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आान किया। उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं और रैलियों के आयोजन से पहले आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए उम्मीदवार लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित एसडीएम कोर्ट रूम में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि रैली और जनसभाओं के लिए निर्धारित स्थानों की जानकारी सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसी प्रकार, चुनाव प्रचार के दौरान बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाने के लिए स्थान और आकार भी तय किए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सेक्टर-14 स्थित स्ट्रॉग रूम का किया निरीक्षण

पंचकूला। नगर निगम चुनाव 2026 को शांतिपूर्वक व पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने के राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय-सेक्टर-14 में स्थित स्ट्रॉग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान चुनाव में प्रयोग में आने वाली ईवीएम मशीनों का भी उपायुक्त ने बारिकी से निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा के साथ डीसीपी श्रीमती सृष्टि गुप्ता व आरओ एवं एसडीएम कालका श्री संयम गर्ग भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूरी टीम के साथ अति संवेदनशील पोलिंग बूथ राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, सेक्टर-17, बूढनपुर, खडक मंगोली व जनेंद्र पब्लिक स्कूल सेक्टर-1 में जाकर इन पोलिंग स्टेशनों का बारिकी से निरीक्षण किया व पुलिस उपायुक्त को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सतपाल शर्मा ने चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों से सख्ती से आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करने की भी अपील की। इस अवसर पर चुनाव कानूनगो कुलदीप व अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

पेक की तकनीकी सोसायटी को अमेरिका के फेयरमोंट स्टेट यूनिवर्सिटी में आयोजित एएससीई कंक्रीट कैनो फाइनल्स के लिए आमंत्रण

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

अमेरिकन सोसायटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स (एएससीई), यूएसए ने पेक के एएससीई स्टूडेंट चैप्टर को 25झ27 जून, 2026 को अमेरिका के फेयरमोंट स्टेट यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रतिष्ठित कंक्रीट कैनो फाइनल्स में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। यह पेक के छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी तकनीकी उत्कृष्टता और इनोवेशन को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह आमंत्रण पेक द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित एएससीई इंडिया सिम्पोजियम (25झ28 मार्च, 2026) के बाद मिला, जिसमें देशभर से लगभग 150 सिविल इंजीनियरिंग छात्र शामिल हुए थे।

2014 में स्थापित एएससीई पेक स्टूडेंट चैप्टर को संस्थान की सबसे सक्रिय तकनीकी सोसायटी में से एक माना जाता है, जिसे बेस्ट स्टूडेंट चैप्टर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग फैकल्टी एडवाइजर अवार्ड, स्टूडेंट लीडरशिप अवार्ड सहित कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। एएससीई पेक स्टूडेंट चैप्टर के फैकल्टी इंचार्ज डॉ. हर अमृत सिंह संधू ने कहा, यह आमंत्रण हमारे छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। यह पेक के सिविल इंजीनियरिंग समुदाय की मेहनत और प्रतिभा को दशार्ता है। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रो. एस.के. सिंह ने टीम को बधाई देते हुए कहा, यह पेक के लिए गर्व का क्षण है। हमारे छात्र न केवल संस्थान का बल्कि भारत का भी प्रतिनिधित्व करेंगे और अंतरराष्ट्रीय टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। उनकी भागीदारी पेक के छात्रों की तकनीकी क्षमता और नेतृत्व कौशल को दशार्ती है। उन्होंने यह भी बताया कि कंक्रीट कैनो की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 0.85 मीटर और गहराई 0.45 मीटर है। पेक के निदेशक प्रो. राजेश भाटिया ने भी टीम को बधाई देते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पेक हमेशा उत्कृष्टता, ईमानदारी और इनोवेशन के मूल्यों पर खड़ा रहा है। हमारे सिविल इंजीनियरिंग छात्रों की यह उपलब्धि दशार्ती है, कि समर्पण, नैतिकता और कड़ी मेहनत वैश्विक पहचान दिलाते हैं। मुझे विश्वास है, कि हमारी टीम पेक के मूल्यों को बनाए रखते हुए देश का नाम रोशन करेगी।

फाइनल्स में पेक का प्रतिनिधित्व करने वाली छात्र टीम में बलकरण सिंह, अर्जुन, विश्वम, वैभव, अंश, दानिश और ईशान शामिल हैं, जिनके साथ उनके फैकल्टी इंचार्ज डॉ. हर अमृत सिंह संधू भी होंगे। यह उपलब्धि पेक की इनोवेशन, टीमवर्क और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दशार्ती है और सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है।

प्रदेश चुनावी खर्च के नोडल अधिकारी ने उम्मीदवारों के चुनावी खर्च के निरीक्षण को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

सिटी दर्पण संवाददात
पंचकूला

नगर निगम चुनाव 2026 को पारदर्शी व शांतिपूर्ण करवाने के लिए प्रदेश चुनावी खर्च के नोडल अधिकारी श्री आशुतोष रंजन ने आज न्यू मिनी सचिवालय सेक्टर-1 में चुनावी खर्च के निरीक्षण को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ डीईटीसी सैल्ज व खर्च पर्यवेक्षक पंचकूला श्री हरवीर सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। प्रदेश चुनावी खर्च नोडल अधिकारी श्री आशुतोष रंजन ने जिले के विभिन्न उम्मीदवारों के चुनावी खर्चों का रेंडमाइजेशन निरीक्षण किया। उन्होंने एसओ, एओ व जिला नोडल अधिकारी चुनावी खर्च को सभी उम्मीदवारों के खर्चों को गहनता से जांच व मॉनिटर करने के निर्देश दिए। उन्होनें बताया कि सभी उम्मीदवारों को आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालना करना चाहिए। उन्होंने जिला की चुनावी खर्च टीम को निर्देश दिए कि सभी उम्मीदवारों के खर्चों को बारिकी से जांचे व रजिस्टर में अच्छे से चैक कर एंट्री मैंटेन करें। इसके अलावा श्री आशुतोष रंजन ने जिले के बार्डर, नाकों का भी निरीक्षण किया व संबंधित अधिकारियों को चुनावी खर्च से संबंधित उचित दिशा निर्देश दिए।

संक्षिप्त-समाचार

पेक के छात्र इमेज प्रोसेसिंग के माध्यम से औद्योगिक समस्याओं के समाधान हेतु नवाचारपूर्ण परियोजना पर कार्यरत

चंडीगढ़। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ इमेज प्रोसेसिंग ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट्स शीर्षक वाली एक परियोजना पर कार्य कर रहा है, जिसे पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कैपस्टोन प्रोजेक्ट एडिशन- के तहत स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस परियोजना में डॉ. सिमरनजीत सिंह (एसोसिएट प्रोफेसर, ईसीई), डॉ. जसकीरत कौर (असिस्टेंट प्रोफेसर, ईसीई) के साथ-साथ छात्र मोनित चावला (बी.टेक चौथा वर्ष) और क्विंसी नामन (बी.टेक तीसरा वर्ष) शामिल हैं। यह परियोजना कास्टिंग उत्पादों के निरीक्षण एवं गुणवत्ता मूल्यांकन हेतु उन्नत इमेज प्रोसेसिंग तकनीकों के उपयोग पर केंद्रित है, जो औद्योगिक चुनौतियों के समाधान और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी।

पंचकूला जिले की मंडियों में सुचारू रूप से चल रहा है गेंहू की खरीद और उठान का कार्य

पंचकूला। जिला में रबी सीजन 2026-27 के दौरान गेंहू की खरीद एवं उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा जिला की मंडियों में से अब तक 35791 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई और 28942 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि सरकारी खरीद एजेंसियों हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा रायपुररानी, बरवाला और पंचकूला स्थित अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4744 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 13083 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7850 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 8484 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। इसके अलावा पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1630 मीट्रिक टन गेंहू की खरीद की गई। उन्होने बताया कि मंडियों में खरीद के साथ साथ उठान का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। रायपुररानी अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 4262 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कोरपोरेशन द्वारा 8860 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। इसी प्रकार बरवाला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 7514 मीट्रिक टन गेंहू और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोशन द्वारा 7301 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया। पंचकूला अनाज मंडी से हैफेड द्वारा 1005 मीट्रिक टन गेंहू का उठान किया गया।

किदार अदबी ट्रस्ट, पंचकूला ने धूमधाम से मनाया विशेष अंतरराष्ट्रीय मासिक काव्य उत्सव

पंचकूला। किदार अदबी ट्रस्ट, पंचकूला ने धूम धाम से मनाई आनलाइन मासिक काव्य गोष्ठी, जिसे काव्य जगत के प्रसिद्ध गुणीजन ने समसामयिक कविताओं से सराबोर कर दिया। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री किदारनाथ किदार जी द्वारा स्थापित किदार अदबी ट्रस्ट, पंचकुला द्वारा हर माह पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली व देश विदेश के साहित्यकारों के लिए काव्य गोष्ठी का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। इस माह की सबरस काव्य गोष्ठी का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन ऑनलाइन जूम माध्यम से किया गया जिसमे ट्राई सिटी के साथ देश विदेश के कवियों/ साहित्यकारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने अपनी अपनी रचनाओं के माध्यम से सभी रंगों की कविताओं की इस काव्य गोष्ठी में अपनी आहुतियाँ दीं। किदार अदबी ट्रस्ट साहित्य के लिए पंचकुला चंडीगढ़ व मोहाली के संबद्ध कवि/ साहित्यकार सदा समर्पित भाव से इस काव्य गोष्ठी के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और समय समय पर साहित्य के अनेक कार्यक्रम करके उनको याद करते रहते हैं, इसी कड़ी में हर महीने उनकी याद में कवि गणेश दत्त अन्य सभी कवियों और साहित्यकारों के सहयोग से काव्य गोष्ठी का हर माह आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले रचनाकार रहे प्रेम विज, अश्वनी कुमार, प्रतिभा सिंह, डॉ संगीता शर्मा कुन्द्रा, सोमेश गुप्ता, पूजा त्यागी, कृष्णा गोयल, सरोज चोपड़ा पद्म, दर्शना सुभाष पाहवा, सुरजीत सिंह धीर, गणेश दत्त बजाज, कृष्णा गोयल, संगीता पुखराज आदि।

ग्लोबल यूथ फेडरेशन ने स्कूल में चार नई कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की

सिटी दर्पण संवाददाता
मोहाली

डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ग्लोबल यूथ फेडरेशन, इंडिया द्वारा मोहाली, पंजाब के सरकारी स्कूलों में चार नए कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं। ये प्रयोगशालाएं ग्लोबल यूथ फेडरेशन द्वारा पुकार झ द वॉइस ऑफ मैनिटी संस्था के सहयोग से तथा सेज फाउंडेशन और आईवॉलंटियर इंडिया के समर्थन से तैयार की गई हैं। इस पहल को मेरा युवा भारत (युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार) को समर्पित किया गया है, जो युवाओं के विकास और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ता है। ये कंप्यूटर प्रयोगशालाएं सरकारी उच्च विद्यालय सनेटा (एस.ए.एस. नगर), सरकारी उच्च विद्यालय मटौर (सेक्टर-70), सरकारी उच्च विद्यालय मौली बैदवान और सरकारी उच्च विद्यालय बलटाना में स्थापित की गई हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और उनकी डिजिटल शिक्षा को मजबूत करना है। यह प्रयास डिजिटल अंतर को कम करने और छात्रों को भविष्य के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने में सहायक होगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई प्रमुख अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें श्री महेश गर्ग (निदेशक, सेज), श्री आनंद कदूर (देश प्रमुख, सेज), सुश्री सुदीप्ति रस्तोगी (प्रशिक्षण एवं विकास प्रमुख तथा वैश्विक सेज फाउंडेशन प्रतिनिधि), प्रो. (डॉ.) रेनू त्रिखा (मुख्य सलाहकार, ग्लोबल यूथ फेडरेशन), श्रीमती गिन्नी दुग्गल (जिला शिक्षा अधिकारी, मोहाली), सुश्री ईशा गुप्ता (जिला युवा अधिकारी, मेरा युवा भारत), श्री रोहित कुमार (निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्लोबल यूथ फेडरेशन) और श्रीमती शिवानी रैना (संस्थापक एवं अध्यक्ष, पुकार झ द वॉइस ऑफ मैनिटी संस्था) शामिल थे। सभी अतिथियों ने इस पहल की सराहना की।

ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह कर्म में दिखाई दे : न्यायमूर्ति ललित बत्रा

सिटी दर्पण संवाददात
पंचकूला

सेक्टर-1 स्थित गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में मंगलवार का दिन विद्यार्थियों के लिए केवल एक औपचारिक समारोह नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत, सपनों और उपलब्धियों का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया। कॉलेज में आयोजित 28वें दीक्षांत समारोह एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम ने स्वामी विवेकानंद सभागार को उल्लास, गर्व और भावनाओं से भर दिया, जहां हर चेहरे पर सफलता की चमक और भविष्य के प्रति नई उम्मीद साफ झलक रही थी। इस गरिमामय आयोजन में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। मंच पर उपस्थित अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति और सभागार में गूंजती तालियों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया।

समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा ने की। अपने प्रेरक संबोधन में न्यायमूर्ति बत्रा ने कहा कि ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह कर्म में दिखाई दे। उन्होंने विद्यार्थियों को यह समझाया कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने का आान किया।

अध्यक्षीय संबोधन में प्राचार्या डॉ. शैलजा छाबड़ा ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह समारोह केवल डिग्री प्रदान करने का अवसर नहीं, बल्कि जीवन में नए अध्याय की शुरूआत है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, विनम्र बने रहने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन एसोसिएट प्रोफेसर हरप्रीत कौर बवेजा द्वारा अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किया गया, जिसने पूरे आयोजन को सजीव और अनुशासित बनाए रखा। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

सारथी स्वयंसेवक केवल मरीजों की सहायता नहीं कर रहे, बल्कि मानवता के सर्वोत्तम रूप को सीख रहे हैं: प्रो. विवेक लाल, निदेशक, पीजीआईएमईआर

पीजीआईएमईआर ने द्वितीय वार्षिक सारथी दिवस मनाया, स्वैच्छिक सेवा और परिवर्तनीय रोगी देखभाल की भावना का सम्मान

सिटी दर्पण संवाददात
चंडीगढ़

एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करते हुए, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ ने आज द्वितीय वार्षिक सारथी दिवस मनाया, जो सारथी के दो सफल वर्षों की स्मृति में आयोजित किया गया–यह एक अग्रणी स्वयंसेवी पहल है जो संस्थान में रोगी देखभाल और पहुंच को रूपांतरित कर रही है। इस अवसर पर श्री एच. राजेश प्रसाद, आईएएस, मुख्य सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि सुश्री प्रेरणा पुरी, आईएएस, सचिव शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन विशिष्ट अतिथि रहीं। कार्यक्रम में प्रो. विवेक लाल, निदेशक, पीजीआईएमईआर, श्री पंकज राय, आईएएस, उप निदेशक (प्रशासन), प्रो. संजय जैन, डीन (अनुसंधान) तथा प्रो. अशोक कुमार, चिकित्सा अधीक्षक भी उपस्थित रहे।

एक भरे हुए सभागार को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री एच. राजेश प्रसाद ने सारथी को सेवा और अनुभवात्मक शिक्षा के अनूठे मॉडल के रूप में सराहा। उन्होंने कहा, सारथी चार सशक्त स्तंभों–सहानुभूति, करुणा, सामाजिक जिम्मेदारी और अनुभवात्मक सीख–पर आधारित है। बड़े अस्पतालों में, जहां व्यवस्थाओं को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये युवा स्वयंसेवक सच्चे सारथी बनकर मरीजों को गरिमा और संवेदनशीलता के साथ मार्गदर्शन देते हैं। यहां उन्हें केवल कौशल ही नहीं, बल्कि जीवनभर के लिए हृदय का परिवर्तन मिलता है। मानवीय सेवा के आयाम को रेखांकित करते हुए उन्होंने आगे कहा, करुणा को पुस्तकों से नहीं सिखाया जा सकता–इसे अनुभव करना पड़ता है। सारथी के माध्यम से ये छात्र न केवल मरीजों की सहायता कर रहे हैं, बल्कि मानवता के वास्तविक सार को भी समझ रहे हैं। यह पहल बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के साथ-साथ बेहतर नागरिक भी तैयार कर रही है।

पहल के व्यापक प्रभाव की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, पीजीआईएमईआर में एक पायलट के रूप में शुरू हुई यह पहल देश के सबसे बड़े सामाजिक सेवा आंदोलनों में से एक बनने की क्षमता रखती है। जब युवाओं की ऊर्जा को सेवा की दिशा में लगाया जाता है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का अनुभव पूरे देश में बदला जा सकता है। इससे पूर्व प्रो. विवेक लाल, निदेशक, पीजीआईएमईआर ने अपने संबोधन में सारथी को संस्थान की करुणा, सेवा और रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा, संस्थान केवल भवनों या तकनीक से नहीं बनते, बल्कि मूल्यों, समर्पण और सेवा से बनते हैं। पीजीआईएमईआर ने अपनी यात्रा इन्हीं मूल्यों के आधार पर तय की है और सारथी इन्हीं आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।

स्वयंसेवकों को स्नेहपूर्वक ब्रेवहार्ट्स संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये युवा केवल मरीजों की सहायता नहीं कर रहे, बल्कि मानवता का श्रेष्ठ रूप सीख रहे हैं। देश के सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक में मरीजों का मार्गदर्शन करते हुए वे सहानुभूति, धैर्य और सेवा के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता विकसित कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में वे सारथी को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय मानेंगे। उन्होंने इस पहल को सफल बनाने में विद्यालयों के प्राचार्यों, शिक्षकों, नोडल अधिकारियों और प्रशासकों के योगदान के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के राष्ट्रीय विस्तार पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, जो पहल पीजीआईएमईआर में शुरू हुई थी, वह अब एक जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है। सारथी ने यह सिद्ध किया है कि जब युवाओं को उद्देश्य और मूल्यों के साथ मार्गदर्शन मिलता है, तो वे परिवर्तन के सशक्त वाहक बन सकते हैं।

श्री पंकज राय, आईएएस, उप निदेशक (प्रशासन), पीजीआईएमईआर ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की चर्चा अक्सर बुनियादी ढांचे और तकनीक तक सीमित रहती है, लेकिन मरीज का वास्तविक अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बड़े संस्थानों में सेवाओं तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है। सारथी इसी अंतर को पाटने के लिए शुरू किया गया था। 6 मई 2024 को शुरू हुई इस पहल के तहत छात्र स्वयंसेवक अस्पताल में मरीजों की गैर-चिकित्सीय प्रक्रियाओं–जैसे पंजीकरण, जांच केंद्रों तक मार्गदर्शन, विभिन्न सेवाओं के बीच आवागमन, तथा बुजुर्ग और कमजोर वर्गों की सहायता–में सहयोग करते हैं। पहल के व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि 2,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने मिलकर 1.24 लाख से अधिक सेवा घंटे दिए हैं, जिससे लाखों मरीजों और उनके परिजनों को लाभ मिला है।

नीतिगत महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सारथी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अनुकरणीय मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा अनुभवात्मक शिक्षण ढांचे के अंतर्गत भी सराहा गया है। उन्होंने कहा, सारथी एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार है और समझती है कि स्वास्थ्य सेवा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह पहल हमें याद दिलाती है कि सच्चा उपचार केवल चिकित्सा में नहीं, बल्कि मरीज को सम्मान और सहारा देने में निहित है। कार्यक्रम में सारथी परियोजना की दो वर्षों की यात्रा का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया। एक विशेष फिल्म के माध्यम से इसके विकास और प्रभाव को दशार्या गया। इसके साथ ही 25 सहयोगी शैक्षणिक संस्थानों को सम्मानित किया गया तथा प्राचार्यों, एनएसएस नोडल अधिकारियों और समर्पित स्वयंसेवकों (ब्रेवहार्ट्स) को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

समापन पर प्रो. संजय जैन, डीन (अनुसंधान), पीजीआईएमईआर ने कहा, सारथी करुणा को क्रियान्वित करने का सशक्त उदाहरण है। यह युवाओं द्वारा संचालित परिवर्तन और सामुदायिक सहभागिता की अपार संभावनाओं को दशार्ता है। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि इस पहल को और मजबूत करते हुए देशभर के स्वास्थ्य संस्थानों में इसका विस्तार किया जाएगा।

स्नूकर विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने वू यीजे

वू यीजे स्नूकर ने ब्रिटेन के शॉन मर्फी को 18-17 से हराया

एजेंसी (हि.स.)
शेफील्ड

वू यीजे स्नूकर विश्व चैंपियनशिप के दूसरे सबसे युवा विजेता बन गए, जब 22 वर्षीय खिलाड़ी ने सोमवार को निर्णायक फ्रेम में ब्रिटेन के शॉन मर्फी को 18-17 से हराया। चीनी खिलाड़ी ने पूर्व चैंपियन मर्फी के खिलाफ कड़े मुकाबले में बढ़त बनाई, जिन्होंने रात भर पीछे रहने के बाद वापसी की और मुकाबले को सोमवार शाम तक खींच लिया।

वू, स्टीफन हेंड्री के बाद यह खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1990 में 21 वर्ष की उम्र में अपना पहला विश्व खिताब जीता था। वह चीन के दूसरे विश्व चैंपियन भी बने, इससे पहले उनके हमवतन झाओ शिंतोंग ने पिछले साल क्रूसिबल में जीत हासिल की थी झाओ को क्वार्टर फाइनल में मैजिशियन मर्फी ने हराया था, जिन्होंने 2005 में अपना पहला विश्व खिताब जीता था, जब वू दो साल के भी नहीं थे। हालांकि, वू ने क्रूसिबल के दर्शकों के वूऊऊ के नारों के बीच शानदार संयम दिखाया। यह फाइनल मुकाबला उतार-चढ़ाव से भरा रहा, जिसमें शाम के सत्र में दोनों खिलाड़ी 14-14, 15-15 और 16-16 की बराबरी पर रहे। वू ने उसी शहर में जीत हासिल की, जहां वह 16 साल की उम्र में अपने स्नूकर करियर को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। मुकाबला निर्णायक फ्रेम तक गया, जहां वू ने सतर्क शुरूआत के बाद नियंत्रण बनाया और 85 का निर्णायक ब्रेक लगाकर जीत सुनिश्चित की। मर्फी ने बीबीसी टू से बातचीत में कहा, मुझे बहुत गर्व है। यह मेरे और मेरी टीम के लिए शानदार कुछ हफ्ते रहे। मैंने शेफील्ड में बेहतरीन समय बिताया। हम बहुत करीब थे, बेहद करीब।

फोटोः हि.स.

उन्होंने कहा, मैं वू यीजे और उनके परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा था कि वह एक दिन विश्व चैंपियन बनेंगे। बस अफसोस है कि वह दिन आज था। ट्रॉफी उठाने के अलावा, जिसकी शुरूआत 1926 में हुई थी, वू को 5 लाख पाउंड (676,400 डॉलर) की पुरस्कार राशि भी मिलेगी और वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंच जाएंगे।

आरसीबी ने 18 साल तक टीम से जुड़े फिजियो इवान स्पीचली को दी भावुक विदाई

विराट कोहली बोले– आप हमेशा परिवार का हिस्सा रहेंगे

एजेंसी (हि.स.)
बेंगलुरु

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने लंबे समय तक टीम के साथ जुड़े रहे पूर्व मुख्य फिजियो इवान स्पीचली को भावुक विदाई दी। स्पीचली ने 2008 से 2025 तक करीब 18 वर्षों तक फ्रेंचाइजी के साथ काम किया और टीम के सबसे पुराने सदस्यों में से एक रहे।

इस खास मौके पर टीम ने बेंगलुरु में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ ने एकत्र होकर स्पीचली के योगदान को याद किया और उनका सम्मान किया।

टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली ने स्पीचली के साथ अपने लंबे रिश्ते को याद करते हुए कहा, मैंने आरसीबी में आपके साथ सबसे ज्यादा समय बिताया है। आप इस टीम के परिवार का हिस्सा हमेशा रहेंगे।

फोटोः हि.स.

टीम के क्रिकेट निदेशक मो बॉबट ने भी स्पीचली के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, इवान लंबे समय तक हमारे मुख्य फिजियो रहे हैं। हम उन्हें वापस बुलाकर उनके योगदान को सम्मान देना चाहते थे और उनके साथ समय बिताना चाहते थे।

भावुक हुए इवान स्पीचली ने भी टीम के प्रति अपना जुड़ाव व्यक्त किया। उन्होंने कहा, जब मैं कल होटल पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे घर वापस आ गया हूं। आरसीबी हमेशा एक परिवार की तरह रहा है। दुनिया का हर क्रिकेटर यहां एक सीजन बिताना चाहेगा, और मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे 18 साल यहां बिताने का मौका मिला।

करीब दो दशकों तक टीम के साथ जुड़े रहे स्पीचली ने कई पीढ़ियों के खिलाड़ियों के साथ काम किया और टीम के भीतर एक भरोसेमंद और सम्मानित चेहरा बने रहे।

आरसीबी की यह विदाई सिर्फ एक व्यक्ति के योगदान का सम्मान नहीं, बल्कि उन लोगों के महत्व को भी दर्शाती है, जो पर्दे के पीछे रहकर टीम की सफलता और संस्कृति को मजबूत बनाते हैं।

विक्टोरिया ने 2026-27 सत्र के लिए टीम घोषित की, ग्लेन मैक्सवेल और मैट शॉर्ट ने राज्य अनुबंध नहीं लिया

एजेंसी (हि.स.)
मेलबर्न

ऑस्ट्रेलिया के घरेलू क्रिकेट में विक्टोरिया ने 2026-27 सत्र के लिए अपनी पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। इस बार सबसे बड़ा फैसला यह रहा कि अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मैट शॉर्ट ने राज्य अनुबंध लेने से इनकार कर दिया है और स्वतंत्र रूप से खेलने का रास्ता चुना है। हालांकि दोनों खिलाड़ी उपलब्ध रहने पर विक्टोरिया के लिए खेलते रहेंगे।

विक्टोरिया टीम पिछले कुछ वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन खिताब जीतने से चूकती रही है। पिछले पांच सत्रों में टीम चार बार फाइनल तक पहुंची, लेकिन हर बार उपविजेता रही। ऐसे में इस बार टीम आठ साल बाद खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। टीम में युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया गया है। ओलिवर पीक को उनके शानदार प्रदर्शन के बाद पहला पूर्ण अनुबंध मिला है, जबकि ऑस्टिन एनलेजार्क और टायलर पियर्सन को भी सीनियर टीम में पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा तेज गेंदबाज हैरी होएक्स्ट्रा को रूकी अनुबंध दिया गया है। उनके साथ आर्यन शर्मा और टॉम पैडिंगटन को भी नए खिलाड़ियों के रूप में शामिल किया गया है। अनुभवी खिलाड़ियों में फर्गस ओ'नील ने टीम के साथ अपना करार बढ़ाया है। वहीं पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर और कैंपबेल केलावे ने भी अनुबंध विस्तार किया है। तेज गेंदबाज सैम एलियट और मिच पेरी को भी पिछले सत्र के शानदार प्रदर्शन के बाद नए अनुबंध से नवाजा गया है। ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने हाल ही में एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, अब टी20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वहीं मैट शॉर्ट भी अंतरराष्ट्रीय और टी20 लीग में सक्रिय रहेंगे। टीम से जे लेमिरे, जेवियर क्रोन और कैलम स्टो को बाहर किया गया है, हालांकि कुछ खिलाड़ियों को टीम के साथ अभ्यास जारी रखने का मौका मिलेगा। क्रिकेट विक्टोरिया के पुरुष क्रिकेट प्रमुख डेविड हसी ने कहा कि टीम में स्थिरता और विकास दोनों देखने को मिल रहे हैं और युवा खिलाड़ियों का उभार टीम के भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत है।

फोटोः हि.स.

विक्टोरिया टीम 2026-27

ऑस्टिन एनलेजार्क, लियाम ब्लैकफोर्ड, स्कॉट बोलैंड, डायलन ब्रैशर, एशले चंद्रसिंघे, हैरी डिक्सन, सैम एलियट, पीटर हैंड्सकॉम्ब, सैम हार्पर, मार्कस हैरिस, कैंपबेल केलावे, ब्लेक मैकडोनाल्ड, कैमरन मैक्लूर, डेविड मूडी, टॉड मर्फी, फर्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, मिच पेरी, टायलर पियर्सन, टॉम रोजर्स, विल सदरलैंड, डग वॉरिन, हैरी होएक्स्ट्रा, टॉम पैडिंगटन, आर्यन शर्मा।

रोहित के शॉट्स मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, हम एक-दूसरे के पूरक हैं: रयान रिकेलटन

मुंबई। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस की शानदार फॉर्म जारी है। सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली छह विकेट की जीत के बाद सलामी बल्लेबाज रयान रिकेलटन ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ अपनी जुगलबंदी और उनसे मिल रही सीख पर खुलकर बात की। रिकेलटन (83) और रोहित (84) की जोड़ी ने इस सीजन की अपनी दूसरी शतकीय साझेदारी निभाकर टीम की जीत की राह आसान की। मैच के बाद रिकेलटन ने कहा कि वह रोहित शर्मा से बल्लेबाजी की बारीकियां सीखने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने बताया, ₹मैंने रोहित से सिर्फ टी20 ही नहीं, बल्कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट की मानसिकता और दबाव झेलने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। वह जिस तरह से शांत रहकर अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं, वह प्रेरणादायक है ₹ रिकेलटन ने मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ा कि रोहित कुछ ऐसे शॉट्स खेलते हैं, जिन्हें खेलना तो दूर, वह उनके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। अपनी सफल सलामी जोड़ी पर बात करते हुए रिकेलटन ने कहा कि दाएं और बाएं हाथ का संयोजन होने के कारण वे एक-दूसरे के पूरक साबित होते हैं।

आईपीएल 2026: ऑरेंज कैप की रेस में शामिल हुए रिकेल्टन

छठे स्थान पर पहुंचे, पर्पल कैप की रेस में भुवनेश्वर कुमार और अंशुल कंबोज संयुक्त रूप से शीर्ष पर

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए मुकाबले के बाद ऑरेंज कैप की रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला। मुंबई के बल्लेबाज रयान रिकेल्टन ने शानदार पारी खेलते हुए एक साथ कई खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया।

रयान रिकेल्टन ने इस मुकाबले में सिर्फ 32 गेंदों पर 83 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसकी बदौलत मुंबई इंडियंस ने जीत हासिल की। इस प्रदर्शन के साथ उनके सीजन में कुल रन 380 हो गए हैं और वह सीधे छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। ऑरेंज कैप की सूची में शीर्ष पांच बल्लेबाजों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा 440 रन के साथ बने हुए हैं, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल 433 रन के साथ मौजूद हैं। तीसरे स्थान पर हेनरिक क्लासेन 425 रन, चौथे स्थान पर वैभव सूर्यवंशी 404 रन और पांचवें स्थान पर गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 385 रन के साथ हैं। रिकेल्टन से पहले 300 से अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लंबी सूची थी, लेकिन उनकी इस पारी ने उन्हें सीधे शीर्ष खिलाड़ियों की कतार में ला खड़ा किया है। फिलहाल मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई अन्य बल्लेबाज शीर्ष 20 में शामिल नहीं है। अब सभी की नजरें केएल राहुल पर हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अगले मैच में खेलेंगे और कुछ चौकों के साथ फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर सकते हैं। वहीं पर्पल कैप की रेस में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। वानखेड़े स्टेडियम की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर गेंदबाजों के लिए ज्यादा मौके नहीं थे और पूरे मैच में केवल नौ विकेट गिरे।

फोटोः हि.स.

लखनऊ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव विकेट लेने में सफल नहीं हो सके, जिससे वह 13 विकेट के साथ छठे स्थान पर ही बने हुए हैं।

पर्पल कैप की रेस में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के भुवनेश्वर कुमार और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज 17-17 विकेट के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। उनके बाद गुजरात टाइटंस के कगिसो रबाडा 16 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर हैं। राजस्थान रॉयल्स के जोफ्रा आर्चर और सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा 15-15 विकेट के साथ क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। अंशुल कंबोज के पास अगले मैच में एक विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में अकेले शीर्ष पर पहुंचने का मौका होगा। आईपीएल 2026 में ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस हर मैच के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है।

एमटीएस में भर्ती, 10वीं पास + तीन साल के अनुभव वालों के लिए मौका

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट (असम) ने सीएसआईआर एनईएसटी भर्ती 2026 के तहत 9 एमटीएस और 1 ड्राइवर पद के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 5 मई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में मल्टी-टास्किंग स्टाफ के कुल 9 पद हैं, जिनमें 4 सामान्य, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 1 एससी और 1 एसटी वर्ग के लिए सीटें रखी गई हैं। इन 9 पदों में से 2 सीटें दिव्यांग और 2 सीटें पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित हैं। वहीं चालक का सिर्फ 1 पद है, जो सामान्य वर्ग के लिए रखा गया है।

आवेदन की शर्तें

मल्टी-टास्किंग स्टाफ पद के लिए उम्मीदवार का सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। अगर किसी ने 12वीं पास की है, तो उसे थोड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं चालक पद के लिए 10वीं पास के साथ एलएमवी और एचएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 3 साल गाड़ी चलाने का अनुभव जरूरी है। साथ ही गाड़ी की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो एमटीएस के लिए अधिकतम उम्र 25 साल और चालक के लिए 27 साल रखी गई है (4 जून 2026 तक)। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी।

नोट करें तिथियां

इवेंट	तिथि
अधिसूचना जारी होने की तिथि	5 मई 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू	5 मई 2026 (सुबह 8:30 बजे)
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	4 जून 2026 (शाम 5:00 बजे)
ट्रेड टेस्ट/स्किल टेस्ट/लिखित परीक्षा	बाद में सूचित किया जाएगा

श्रेणीवार आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन जमा करना होगा। सामान्य, ओबीसी और एहर वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, पूर्व सैनिक, महिला उम्मीदवार और CSIR कर्मचारियों को कोई शुल्क नहीं देना है।

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले की आधिकारिक वेबसाइट neist.res.in पर जाएं।
होमपेज पर "Recruitment" या "Career" सेक्शन खोलें।
CSIR NEIST MTS/Driver भर्ती 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
"New Registration" पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करें।
लॉगिन करके आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें।
जरूरी दस्तावेज (फोटो, सिग्नेचर आदि) अपलोड करें।
आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) SBI Collect के माध्यम से जमा करें।
फॉर्म सबमिट करें और उसका एक प्रिंट या पीडीएफ ले लें।

एएसओ व एआरओ के 929 पदों के लिए उम्मीदवार 11 तक कर सकते हैं आवेदन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) और असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर (ARO) के कुल 929 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन विंडो जल्द ही बंद होने वाली है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे 11 मई 2026 तक अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें। इसमें सबसे पहले PET 2025 स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही वे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और यह परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

समझें चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सबसे पहले उम्मीदवारों का चयन PET 2025 स्कोर के आधार पर किया जाएगा, इसलिए PET परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इसके बाद PET में प्राप्त अंकों के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदर्शन ही आगे के चयन का आधार होगा। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चरण दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जहां सभी प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही अंतिम चयन किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले उम्मीदवारों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। होमपेज पर दिए गए "ASO-ARO Recruitment 2026" लिंक पर क्लिक करें। अब अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के माध्यम से लॉगिन करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें और सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें। आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें। यदि आवेदन शुल्क लागू हो, तो उसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें। अंत में फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

10वीं पास 18 मई तक कर सकते हैं वॉचमैन के 416 पदों पर आवेदन

महाराष्ट्र के नासिक स्थित जनजातीय विकास विभाग द्वारा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चौकीदार पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 416 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 18 मई 2026 तक जारी रहेगी।

10वीं पास करें आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास (SSC) होना जरूरी है। यानी आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 38 साल है। SC/ST/OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 43 साल, दिव्यांग (PwBD) के लिए 45 साल, और पूर्व सैनिकों को सेवा अवधि के साथ 3 साल की छूट दी गई है (अधिकतम 45 साल तक)। इसके अलावा अनाथ उम्मीदवारों के लिए उम्र 43 साल और अंशकालिक कर्मचारियों के लिए 55 साल तक रखी गई है।

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, यानी एक बार फीस भरने के बाद रिफंड नहीं मिलेगा। उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए करना होगा। शुल्क की बात करें तो सामान्य (ओपन) वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये देना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग, एहर, अनाथ और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 900 रुपये (10% छूट) निर्धारित है। पूर्व सैनिक और विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी वे मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में सबसे पहले कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, जो कुल 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ (MCQ) परीक्षा होगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट बनाई जाएगी, जो उम्मीदवार तय कट-ऑफ और न्यूनतम अंक (सामान्य वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40%) से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उम्मीदवारों के सभी जरूरी प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी।

वेतन 47 हजार तक

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान S-1 के अनुसार सैलरी दी जाएगी। चौकीदार (वॉचमैन) पद के लिए मासिक वेतन 15,000 से 47,600 के बीच निर्धारित किया गया है। इसके अलावा उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते भी मिलेंगे, जिससे कुल सैलरी और सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं।